₹ 10

www.kewalsachtimes.com

अगस्त 2026

KEWAL SACH TIMES

A National Magazine

RNI NO.-BIHBIL/2011/49252, DAVP NO.-131729, POSTAL REG. NO.:-PS-78

छात्र आंदोलन : जिसने झुका दी सरकार

प्रधान का इस्तीफा

छात्रों की जीत

जन-जन की आवाज है केवल सच

केवल सच
हिन्दी मासिक पत्रिका

Kewalsachlive.in
वेब पोर्टल न्यूज
24 घंटे आपके साथ

Kewalsach news
Kewalsach news
Mob.: 9431073769, 9308815605
खबर वहीं,
जो केवल सच हो

केवल सच TIMES

आत्म-निर्भर बनने वाले युवाओं को सपोर्ट करें

आपका छोटा सहयोग, हमें मजबूती प्रदान करेगा

BHIM | UPI
G Pay Paytm

www.kewalsach.com www.kewalsachlive.in

-: सम्पर्क करें :-

पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, मकान संख्या-28/14,
कंकड़बाग, पटना (बिहार)-800020, मो०:-9431073769, 9308815605

जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ

काजोल
05 अगस्त 1974

वेंकटेस प्रसाद
05 अगस्त 1969

कपिल सिब्बल
08 अगस्त 1948

महेश बाबू
09 अगस्त 1975

सुनील शेट्टी
11 अगस्त 1961

सीताराम येचुरी
12 अगस्त 1952

स्व०श्रीदेवी कपूर
13 अगस्त 1963

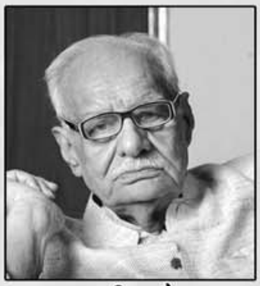

कुलदीप नैयर
14 अगस्त 1923

सुनीधी चौहान
14 अगस्त 1983

अदनान सामी
15 अगस्त 1973

अरविन्द केजरीवाल
16 अगस्त 1968

सैफ अली खान
16 अगस्त 1970

दलेर मेंहदी
18 अगस्त 1967

स्व०राजीव गांधी
20 अगस्त 1944

रणदीप हुड्डा
20 अगस्त 1976

चिरंजिवी
22 अगस्त 1955

मधुर भंडारकर
26 अगस्त 1966

मेनका गांधी
26 अगस्त 1956

दिलीप सिंह खली
27 अगस्त 1972

अक्केनी नार्गाजुन
29 अगस्त 1959

KEWAL SACH TIMES

A National Magazine

Regd. Office :-
East Ashok, Nagar, House No.-28/14, Road No.-14, kankarbagh, Patna- 8000 20 (Bihar) Mob.-09431073769,
E-mail :- kewalsach@gmail.com

Corporate Office:-
Vaishnavi Enclave, Second Floor, Flat No. 2B, Near-firing range, Bariatu Road, Ranchi- 834001
E-mail :- editor.kstimes@rediffmail.com

Delhi Office :-
Sanjay Kumar Sinha
A-68, 1st Floor, Nageshwar talla, Shastri Nagar, New Delhi-110052
Mob.- 09868700991, 09955077308
kewalsach_times@rediffmail.com

Kolkata Office :-
Ajeet Kumar Dube,
131 Chitranjan Avenue, Near- md. Ali Park, Kolkata- 700073 (West Bengal)
Mob.- 09433567880, 09339740757

ADVERTISEMENT RATES PER ISSUE

COLOUR

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
Cover Page	3,00,000/-	N/A
Back Page	1,00,000/-	65,000/-
Back Inside	90,000/-	50,000/-
Back Inner	80,000/-	50,000/-
Middle	1,40,000/-	N/A
Front Inside	90,000/-	50,000/-
Front Inner	80,000/-	50,000/-

B & W

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
Inner Page	60,000/-	40,000/-

1. एक साल के नियमित विज्ञापन पर पत्रिका के वेवसाइट **www.kewalsachtimes.com** के फ्रंट पर भी विज्ञापन निःशुल्क तथा आपका वेवसाइट से सीधा लिंक हो सकता है।
2. एक साल के नियमित विज्ञापन पर 10 प्रतिशत की रियायत।
3. आपके प्रोडक्ट या संगठन के प्रचार-प्रसार हेतु आलेख को उचित स्थान।
4. पत्रिका द्वारा सामाजिक कार्य में आपके संगठन/प्रोडक्ट का बैनर/फ्लैक्स को उचित स्थान देकर आपके संगठन का व्यापक प्रचार-प्रसार।
5. विज्ञापन का भुगतान चेक या आर.टी.जी.एस. से ही मान्य होगा।

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

आन्दोलन, आजादी या गुंडागर्दी

अपनी प्रतिक्रिया हमारे ई-मेल पर दें:- editor.kstimes@rediffmail.com

आजाद भारत के लोकतांत्रिक देश में 1974 के आन्दोलन के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ और इंदिरा गांधी की कांग्रेस की सरकार गिर गई थी लेकिन 2026 में हुए जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी CJP ने युवाओं को लेकर ऐसा आन्दोलन किया कि केन्द्रीय शिक्षा मंत्री एवं भाजपा के दिग्गज राजनेता धर्मेन्द्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा और आन्दोलन समाप्त हुआ। सोनम वामचुंग के भूख हड़ताल ने नरेन्द्र मोदी की साख पर प्रश्नचिन्ह् उठा दिया है। विभिन्न जाति एवं विभिन्न पार्टियों के युवाओं ने UGC 2026 के कानून को लेकर गोलबंद हो गये और परिणाम विधानसभा के उप चुनाव में भी देखने को मिला। कॉकरोच जनता पार्टी ने आन्दोलन को सजाया और 12 साल की मोदी सरकार की नींद हराम करके रख तो दिया लेकिन जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल लड़कियों ने किया है उससे आन्दोलन भी शर्मसार हुआ और आन्दोलन के समाप्त होने के बाद उन लड़कियों को भी इसका एहसास हुआ। आजादी के नाम पर जिस प्रकार का आन्दोलन में वातावरण देखा गया वह आजाद भारत को शर्मसार करने के लिए काफी है। आन्दोलन के नाम पर गुंडागर्दी का भी दौर चला साथ ही आन्दोलन में तिलक - तराजू और तलवार को भी ललकारा गया। आन्दोलन के आड़ में गुंडागर्दी भी किया गया तो पुलिस ने भी अपनी मर्यादा को भूलकर मानवाधिकार का भरपूर हनन किया। 1974 के आन्दोलन की तरह पूरे भारत में 2026 में आन्दोलन युवाओं के नेतृत्व में हुआ पर आपात काल की तरह उसका मुकाबला करना आन्दोलनकारियों के वश की बात नहीं थी। जनता भी मोदी सरकार के UGC 2026 कानून को लेकर असमंजस की स्थिति में दिखी।

एक लड़की ने सोसल मीडिया पर यह कहा कि ''**जितनी महिलाओं का पिरियड में जितना लिक नहीं होता उससे कहीं ज्यादा पेपर लीक हो रहा है**'' सही मायने में सरकार को इससे घिनौने शब्दों से कभी विपक्ष निशाना नहीं साधा होगा। भारत देश में समय - समय पर सरकार के तानाशाही एवं उदासीन रवैय्ये के विरूद्ध आन्दोलन होते सम्पूर्ण क्रान्ति या ''जेपी आन्दोलन'' या ''बिहार आन्दोलन'' सन् 1974 में बिहार में छात्रों द्वारा आरम्भ किया गया एक आन्दोलन था जो इस राज्य के कुशासन एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। गुलामी की जंजीर में बंधी भारत 10 अप्रैल 1917 भारत के स्वतंत्रता संग्राम का वह ऐतिहासिक दिन बना, जब एक शांतिपूर्ण आंदोलन ने देश की दिशा बदल दी। इसी दिन बिहार के चंपारण से महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की। यह भारत में उनका पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जिसने आगे चलकर आजादी की लड़ाई को नई ऊर्जा दी। इन 90 वर्षों में, स्वदेशी आंदोलन, स्वशासन आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन सहित कई प्रमुख आंदोलनों ने संघर्ष को आकार दिया था। भारत की गुलाम जनता गुलाम भारत में एकजुट होकर आन्दोलन में खड़ी रही लेकिन आजादी के बाद के आन्दोलनों में जनता जाति, धर्म और पार्टी को देखकर आन्दोलन का हिस्सा बनती है। ज्ञात हो कि 5 अप्रैल 2011 को एक सशक्त लोकपाल विधेयक के निर्माण की माँग पर सरकारी उदासीनता एवं निष्क्रियता के विरोध में अन्ना हजारे ने आमरण अनशन शुरु कर दिया था और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी इस मुहिम में अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, प्रशांत भूषण, बाबा रामदेव एवं अन्य अनेक प्रसिद्ध समाजसेवी शामिल हुए थे और सरकार को उनकी जायज मांगों को मानना पड़ा था। कॉकरोच जनता पाटी का आन्दोलन वास्तव में अन्ना आंदोलन से बड़ा इसलिए भी है क्योंकि यह स्वयं चल रहा है और 20 जुलाई को जितने लोग यहां आए थे, वह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आन्दोलन में शामिल हुए छात्रों की नाराजगी से स्पष्ट होता है कि मोदी सरकार से भारत के छात्र नाराज हैं और गलत नितियों का विरोध करने के लिए दलगत राजनीति से उपर उठकर समर्थन कर रहे थे। यूजीसी और पेपर लीक के मामले ने देश के युवाओं को सोचने पर मजबूर कर दिया कि सरकार राजनीति फायदे के लिए हमें आपस में लड़ाना चाहती है लेकिन इसके बावजूद तिलक-तराजू और तलवार के नारे में आन्दोलन में गूंजते रहे। 16 मई 2026 को **अभिजीत दिपके** द्वारा कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना की गई महज दो महीने में इसने देश के बच्चे-बच्चे तक अपनी पहचान बना ली। 12 साल की 56 इंच की साख को एक झटके में हिल्लाकर रख दिया। अभिजीत दिपके राजनीतिक संचार रणनीतिकार हैं और पहले अरबिन्द केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के साथ काम कर चुके हैं। देश के भीतर जब भी कोई ऐसा कार्य किया जाता है जो देश एवं जनहित में नहीं हो तो आन्दोलन करके सरकार का ध्यान समस्या पर आकृष्ट कराया जाता है। अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से लेकर किसानों, छात्रों और कर्मचारियों के प्रदर्शन तक जंतर-मंतर ने भारतीय लोकतंत्र के कई ऐसे निर्णायक क्षण देखे हैं जहां से योग बाबा रामदेव को लड़की के सलवार-सूट में स्टेज से कूदकर जान बचाने के लिए भागना पड़ा था। वर्ष 2026 में नीट परीक्षा पेपर लीक के मामले पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धमेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने यहां आंदोलन शुरू किया, जिसमें 28 जून को वैज्ञानिक, पर्यावरणविद् और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पहचान रखने वाले सोनम वांगचुक ने यहीं पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दिया और 17 दिनों के बाद जब उनकी स्थिति बहुत अधिक खराब होने लगी तो बड़ी संख्या में छात्र और युवा इस प्रदर्शन का हिस्सा बनने लगे। जंतर-मंतर के अलावा देश के विभिन्न राज्यों में इस आन्दोलन को गति। इस आन्दोलन में शांति के साथ गुंडागर्दी का भी परिचय आन्दोनकारियों ने दिया और स्थिति नेपाल की तरह बनने लगी। सोसल मीडिया ने इस आन्दोलन को विश्व के पटल पर पहुंचा दिया और भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की छवि को धूमिल कर दिया गया। सरकार अपनी फजीहत होता देख धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया और आन्दोलन को समाप्त करवाया गया लेकिन इस आन्दोलन में छात्र एवं छात्राओ ने पीएम पर गंदी एवं भद्दी शब्दों से इतना प्रहार किया कि पीएम को मध्यरात्रि में सोसल मीडिया पर आकर अपनी बात कहनी पड़ी। कॉकरोच जनता पार्टी प्रमुख अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण छात्र विरोध प्रदर्शन में बाहरी लोगों को जान-बूझकर घुसपैठ कराया गया था ताकि आन्दोन में खुलेआम गंडागर्दी हो और छात्रों की मांग को गलत ठहराया जा सके। 20 जुलाई, 2026 को संसद भवन मार्च के दौरान भयंकर हिंसा हुई जिसमें बाहरी लोगों को पुलिस के समर्थन में खड़ा किया गया और जमकर छात्रों पर जानलेवा हमला हुए और इनलोगों की दिल्ली पुलिस से मिलीभगत थी अन्यथा जिस प्रकार की गुडागर्दी हुई उसको दिल्ली पुलिस रोक सकती थी। सत्ता के मद्द में चूर जब सरकार तानाशाह बनकर काम करती है तो युवाओं को आगे आना ही पड़ता है। 1974 के 52 साल बाद पहली बार फिर से देश के छात्र गोलबंद हुए और अपनी शक्ति का एहसास कराया।

KEWAL SACH TIMES
A National Magazine
वर्षः- 16, अंकः- 182 माहः- अगस्त 2026 रू. 10/-

Editor

Brajesh Mishra 9431073769
6206889040
8340360961

editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach@gmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

Principal Editor

Arun Kumar Banka 7782053204
Nilendu Kumar Jha 9431810505

General Manager (H.R)

Triloki Nath Prasad 9308815605

General Manager (Advertisement)

Manish Kamaliya 6202340243
Poonam Jaiswal 9430000482

Joint Editor/Lay-out Editor

Amit Kumar 9905244479
amit.kewalsach@gmail.com

Legal Editor

Amitabh Ranjan Mishra 8873004350
S. N. Giri 9308454485

Asst. Editor

Mithilesh Kumar 9934021022
Sashi Ranjan Singh 9431253179
Rajeev Kumar Shukla 7488290565

Sub. Editor

Arbind Mishra 6204617413
Prasun Pusakar 9430826922

Bureau Chief

Sanket kumar Jha 7762089203

Bureau

Sridhar Pandey 9852168763
Sonu Kumar 8002647553

Photographer

Mukesh Kumar 9304377779

प्रदेश प्रभारी

दिल्ली हेड

संजय कुमार सिन्हा 9868700991

झारखण्ड हेड

ब्रजेश मिश्र (2) 7979769647
7654122344

पश्चिम बंगाल हेड

अजीत दुबे 9433567880
9339740757

मध्यप्रदेश हेड

अभिषेक पाठक 8109932505
8269322711

छत्तीसगढ़ हेड

आवश्यकता है

उत्तर प्रदेश हेड

निर्भय कुमार मिश्रा 9452127278

उत्तराखण्ड हेड

आवश्यकता है

महाराष्ट्र हेड

आवश्यकता है

गुजरात हेड

आवश्यकता है

आंध्र प्रदेश हेड

आवश्यकता है

राजस्थान हेड

आवश्यकता है

पंजाब हेड

आवश्यकता है

हरियाणा हेड

आवश्यकता है

राजस्थान हेड

आवश्यकता है

उड़ीसा हेड

आवश्यकता है

आसाम हेड

आवश्यकता है

हिमाचल हेड

आवश्यकता है

दिल्ली कार्यालय

केवल सच टाइम्स,
द्विभाषीय मासिक पत्रिका,
द्वारा- संजय कुमार सिन्हा
A-68, 1st Floor,
नागेश्वर तल्ला, शास्त्रीनगर, न्यू दिल्ली-110052
मो०- 9868700991, 9431073769

पश्चिम बंगाल कार्यालय

केवल सच टाइम्स,
द्विभाषीय मासिक पत्रिका,
द्वारा- अजीत कुमार दुबे
131 चितरंजन एवेन्यू,
कोलकात्ता, पश्चिम बंगाल- 700073
मो०- 9433567880, 9339740757

झारखण्ड कार्यालय

केवल सच टाइम्स,
द्विभाषीय मासिक पत्रिका,
वैष्णवी इंक्लेव, द्वितीय तल,
फ्लैट नं- 2बी
नियर- फायरिंग रेंज
बरियातु रोड, राँची- 834001
मो०- 9308815605

मध्यप्रदेश कार्यालय

केवल सच टाइम्स,
द्विभाषीय मासिक पत्रिका,
द्वारा- अभिषेक कुमार पाठक
हाउस नं.-28, हरसिद्धि कैम्पस
खुशीपुर, चांबड़
भोपाल, मध्य प्रदेश- 462010
मो०- 8109932505,

विशेष प्रतिनिधी

भारती मिश्र 8521308428
बेंकटेश कुमार 8210023343
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

प्रकाशित आलेख पर आप अपना सुझाव एवं प्रतिक्रिया अवश्य दें।

केवल सच टाइम्स

द्विभाषीय मासिक पत्रिका

हमारा पता है

पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14,
मकान संख्या:- 14/28, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)
सम्पर्क करें:- 9431073769, 8340360961

हमारा ई-मेल

editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

जुलाई 2026

संकट

मिश्रा जी,

जुलाई 2026 अंक का आपका संपादकीय "**संकट में है बिहार**" में बिहार की राजनीति सहित प्रशासनिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण से किस स्थिति में है उसका पूरा उल्लेख करते हुए लिखा है। आपकी लेखनी जिवंत हैं और सरलता के साथ लिखने की वजह से आमजनों को खुद की लेखनी है जैसा महसूस कराने की आपकी कला को मैं साधुबाद देता हूं। बिहार सही मायने में संकट में है और हमारे युवा जीविका के लिए पलायन को आज भी मजबूर हैं। बेहतरीन शिक्षा एवं तंदरूस्त स्वास्थ व्यवस्था भी आजादी के 80 साल में सुदृढ़ नहीं हो सकी। इस प्रकार का जागरूकता फैलाते रहिए।

● **राजीव रंजन मिश्र, गायघाट, पटना**

प्रशासन

संपादक महोदय,

केवल सच टाइम्स, पत्रिका के जुलाई 2026 अंक में "**टूटती सांसे, सुलगते सवाल, मुआवजे और पुनर्वास कब जागेगा प्रशासन?**" में केन बेतवा संघर्ष की पूरी कहानी को सहीं ढ़ंग से लिखा गया है। न्याय दो या मार दो के नारे के साथ लंबे संघर्ष को किया जाना वास्तव में लोकतंत्र की खूबसूरती है। आपकी पत्रिका विभिन्न मुद्दों को पूरी गंभीरता एवं प्रमाण के साथ खबरों को पाठकों एवं सरकार के बीच रखती है। कई मामले में सरकार इसपर संज्ञान भी लेती है। "केवल सच" पत्रिका एवं "केवल सच टाइम्स" पत्रिका और पोर्टल न्यूज kewalsachlive.in भी खबरों को प्रकाशित करता है।

● **रौशन सिंह, रोड नं-4, अशोक नगर, नई दिल्ली**

कब मिलेगा न्याय

संपादक महोदय,

केवल सच टाइम्स पत्रिका के जुलाई 2026 अंक में भोजपुर जिला में हुए भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर पर सटीक समीक्षात्मक खबर को प्रकाशित किया गया है। अमित कुमार की खबर "**भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर या हत्या, कब मिलेगा न्याय?**" में पूरे मामले की पड़ताल के साथ, इस घटना के कारण की जानकारी को भी बारीकी के साथ लिखा है। भरत भूषण तिवारी की हत्या या एनकाउंटर के साथ, भरत तिवारी के सामाजिक कार्यों को भी गांव सहित जिला के लोगों ने भी स्वीकार्य किया है। आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा निर्गत राशि का मामला भी भरत तिवारी के प्रकरण में अहम भूमिका रही है। खबर जानकारीप्रद है।

● **प्रदीप सिंह, उदवंत नगर, भोजपुर, बिहार**

मर्डर

संपादक महोदय,

केवल सच टाइम्स पत्रिका के जुलाई 2026 अंक में प्रकाशित खबर "**लोहगढ़ फोर्ट मर्डर मिस्ट्री**" में हत्या में मंगेतर हीं अहम भूमिका में शामिल थी की जानकारी मिला की बात सोचकर सिहरन हो जाता है। कंचन अग्रवाल की हत्या महज 26 वर्ष की उम्र में जिससे शादी होनी वाली थी उसी ने कर दी की घटना काफी शर्मनाक है। वहीं दूसरी खबर "**5 दिन में बाबा बर्फानी अंर्तध्यान!**" भी काफी पठनीय एवं संग्रहनीय है। अमरनाथ गुफा में कैसे बनता है बर्फ का शिवलिंग? की सटीक जानकारी पढ़कर मन को शांति मिली। आपकी पत्रिका एक तरफ मर्डर की हिस्ट्री की खबर तो दूसरी तरफ शिवलिंग के बर्फ की जानकारी भी जन-उपयोगी होता है।

● **रोहित वर्णवाल, भोपाल रेलवे कॉलनी, भोपाल**

खजाना

मिश्रा जी,

मैं **केवल सच टाइम्स** पत्रिका का नियमित पाठक हूं। जुलाई 2026 अंक में अमित कुमार की खबर "**हे राम! कैसे किया ये काम?**" जब चौकीदार हीं चंपत, तो फिर खजाना कैसे बचेगा? में अयोध्या में स्थित राम मंदिर के पूरे चंदे के मामला को लेकर देश के भीतर राजनीतिक एवं धार्मिक माहौल खराब होता जा रहा है तथा मोदी एवं योगी की सरकार का इमेज खराब हो रहा है। पूरे मामले को विस्तार से समीक्षात्मक ढ़ंग से अमित कुमार ने खबर को सजाया एवं ज्वलंत मुद्दे को परत दर परत रखने की सार्थक पहल की है। ऐसी खबर पाठकों के बीच समन्वय बनाने में सफल साबित होता है। राम मंदिर की दानपेटी की सुरक्षा पर सटीक आलेख है।

● **जितेन्द्र सहाय, लंका कॉलोनी, बनारस, यूपी**

कलंक

ब्रजेश जी,

जुलाई 2026 अंक में प्रकाशित खबर "**नितिन नविन के गाड़ी के आगे नाचे हनुमान**" में बिहार के पटना जिला के बांकीपुर विधानसभा उप चुनाव के प्रचार के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नविन स्वयं गाड़ी पर अपने नेताओं के साथ खड़े थे वहीं सड़क पर हनुमान जी के मुखौटा में एक आदमी नाच रहा था। इस मामले को देश के विपक्षी राजनेताओं ने आड़े हांथों लेते हुए कहा कि भाजपा का अहंकार इस कदर बढ़ता जा रहा है कि भगवान को भी नचवाया जा रहा है। अरबिन्द केजरीवाल ने भड़कते हुए कहा कि हिन्दू धर्म पर कलंक हैं ये लोग। प्रत्याशी जनसुराज प्रशांत किशोर ने इसको बड़ा मुद्दा बनाकर वोट को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। सटीक खबर

● **गणेश गुप्ता, मछली गली, परन्दपुर, पटना**

अन्दर के पन्नों में

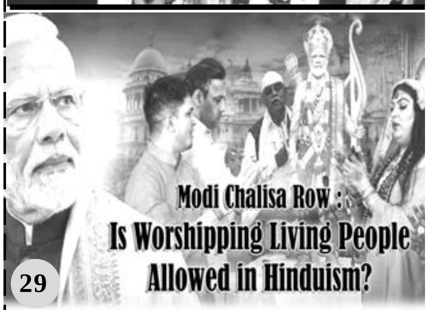

श्री चन्द्र प्रकाश सिंह

प्रधान संरक्षक सह प्रबंध संपादक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक)

पूर्व निदेशक सदस्य, ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स

09431016951, 09334110654

डॉ. सुनील कुमार

शिशु रोग विशेषज्ञ सह मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका

एवं 'केवल सच टाइम्स'

एन.सी.- 115, एसबीआई ऑफिसर्स कॉलोनी,

लोहिया नगर, कंकड़बाग, पटना- 800020

फोन- 0612/3504251

सुधीर कुमार

मुख्य संरक्षक सह निदेशक "**मगध इंटरनेशनल स्कूल**" टेकारी

" **केवल सच** " पत्रिका **एवं " केवल सच टाइम्स "**

9060148110

sudhir4s14@gmail.com

कैलाश कुमार मौर्य

मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

व्यवसायी

पटना, बिहार

7360955555

एक नजर

संपादकीय व प्रधान कार्यालयः-

☞ पूर्वी अशोक नगर, रोड नं:-14, मकान संख्या:- 28/14, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)

e-mail:- kewalsach@gmail.com,
editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

☞ स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक ब्रजेश मिश्र द्वारा जय हिन्द प्रेस कंकड़बाग पटना-800020 से मुद्रित एवं पूर्वी अशोक नगर, रोड नं. 14, कंकड़बाग पटना-800020 से प्रकाशित, संपादक- ब्रजेश मिश्र। **RNI NO.- BIHBIL/2011/49252**

☞ पत्रिका में प्रकाशित समाचारों से संपादक की सहमति आवश्यक नहीं है।

☞ सभी प्रकार के वाद - विवादों का निपटारा पटना न्यायालय के अधीन होगा।

☞ आलेख पर किसी को कोई आपत्ति हो तो एक महीने के भीतर खंडन करें।

☞ किसी भी लेख के लिए रचनाकार/लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

☞ सभी पद अवैतनिक हैं।

☞ विज्ञापन की सत्यता की जाँच आप अपने स्तर पर कर लें।

☞ फोटो-समाचार साभार भी (माध्यम- इंटरनेट एवं अन्य स्त्रोत)

☞ कोई भी शिकायत हमारे पते पर लिखकर भेजें।

☞ **विज्ञापन का भुगतान चेक या ड्राफ्ट एवं RTGS से ही मान्य होगा।**

☞ भुगतान BRAJESH MISHRA को ही करें। किसी प्रतिनिधि को नगद न दें।

☞ A/C No.	:-	20001817444
BANK	:-	State Bank Of India
IFSC Code	:-	SBIN0003564
PAN No.	:-	AKKPM4905A

Contributions/Donations are Invited for the Welfare of Elders/Sr. Citizens for the establishment of
"APNA GHAR" A home for Sr. Citizens of Bihar & Jharkhand Proposed to be Constructed
Under the ageas of " KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN".
KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN
Registered Under the Indian Society Act 21, 1880
East Ashok Nagar, Road No.-14,
Kankarbagh, Patna - 800020
Contact No. :- 09431073769, 9955077308, 9308727077
E-mail :- kewalsachsamajiksansthan33@gmail.com
Reg. No. : 1141 (2009-10), Income Tax No. :12AA/2505-8 | 80 जी (5)/तक०/2013-14/1060-63
APNA GHAR
Now in the State of Bihar & Jharkhand
Help the helpless Elders/Sr. Citizen. For which your
Contribution and Donation are essential.
Your Coopertation in this direction can make a diffrence
in the lives of many Sr. Citizens.
KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN
A/C No. - 0600010202404
Bank Name - United Bank of India
IFSC Code - UTBIOKKB463
Pan No. - AAAAK9339D

छात्र आन्दोलन : जिसने झुका दी सरकार

प्रधान का इस्तीफा छात्रों की जीत

● **अमित कुमार**

'सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीनती है और फिर उन्हीं को चश्मा दान करती है'। आज पूरा देश जेन-जी बना बैठा है, खुद को कॉकरोज कहकर उग्र आंदोलन किया और अभी तक कर ही रहा है। इस छात्र आंदोलन में छात्र और पुलिस दोनो ही गंभीर रूप से चोटिल भी हुए किन्तु जब ये सब हो रहा था तब देश का चौकीदार चुपचाप यह देख रहा था। अब सियासत पर बात करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर बात कर लेना जरूरी है और इस चुप्पी को समझने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को याद करना पड़ेगा। वह मनमोहन सिंह, जिन्हें दस साल तक देश ने 'मौनमोहन' सिंह कहकर मजाक उड़ाया। क्योंकि वह 2जी घोटाले पर खामोश थे, कोयला पर खामोश थे, कॉमनवेल्थ गेम्स पर खामोश थे। हर बड़े मसले पर खामोश थे और तब सारा देश कहता था कि प्रधानमंत्री बोलते क्यों नहीं हैं? आज हम और आप 2026 में हैं, लेकिन सवाल वही है, बस नाम बदला है। आज भी जनता पूछ रही है कि मोदी जी आप चुप क्यों हैं? यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि सड़क से लेकर संसद तक जो कुछ दिखा वो तीस-पचास साल में दिखा नहीं था। अफरा तफरी चारों तरफ थी। लाठीचार्ज हो रहा था, छात्र लाठियां खा रहे थे, पुलिसवालों को भी चोट आ रही थी। भीड़ में पत्थर चल रहे थे, बैरिकेड टूट रहे थे। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में जो कुछ हुआ था, उसकी झलकियां दिखाई पड़ रही थी। मेट्रो से लेकर सड़क तक अफरा तफरी थी और ऐसा लगा कि आज फिर से जनता को एहसास हुआ कि संसद का रास्ता जो है वो सड़क से होकर जाता है, इसके बाद जो तस्वीरें आईं वो ऐतिहासिक थीं। वो ये बता रही थी कि नई संसद की दीवारें भले ऊंची बनाई गई हैं, लेकिन इतनी भी ऊंची ठीक नहीं है कि आवाज ही न पहुंचे। इमारत नई हो सकती है, लेकिन सवाल वही पुराना है कि जनता से संसद है और संसद जनता से इतनी ऊंची ना हो जाए कि वो न सुन पाए। अगर नहीं सुन पा रहे तो फिर क्या शोर मचाना जरूरी है? और क्या वो शोर जानबूझकर नहीं सुना गया या जानबूझकर अनसुना कर दिया गया? या वो आवाजें पहुंची नहीं, क्योंकि सड़क पर गुस्सा था। प्रधानमंत्री को सब पता था और प्रधानमंत्री संसद में थे भी। लेकिन इन तस्वीरों

पर बोलने की जगह वो राहुल गांधी की उम्र का मजाक उड़ाकर चले गए। वो सिर्फ अट्ठाईस साल के हैं, किसी छप्पन साल के नौजवान की बात नहीं हो रही! वहीं से यह सवाल आने लगा कि प्रधानमंत्री जी आप बात कर सकते थे। आप क्यों खामोश रहते हैं? 2014 से 12 साल हो गए। 12 सालों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप आए, वो भी अमित शाह बोलते रहे। आप हर बड़े मसले पर खामोश होते हैं और इस बार तो बच्चे थे। अंग्रेजों के जमाने में भी गांधी जी से वो बात करते थे। वो दुश्मन थे। ये राजनीतिक विरोधियों के साथ खड़े बच्चे थे। ये दुश्मन नहीं थे। आप इनसे क्यों नहीं बात कर सकते थे?

आज सवाल एहसास का है। वो एहसास जो टपरी से उठकर सड़क संसद तक पहुंचा। वो एहसास जो सरकार के विरोधियों के साथ-साथ सरकार के अपने लोगों में भी पहुंचा और आज हर कोई देश में पूछ रहा है कि मोदी जी बात तो कर सकते थे, इसमें क्या ऐसा था? कितने सारे लोगों की खून बहा। कितने लोग चोटिल हुए। कितना नुकसान हुआ। देखिए शुरुआत में मैंने कहा था कि मान लेते हैं कि यह प्रोटेस्ट राजनीतिक है। कहा जा रहा है कि भीम आर्मी, आयसा, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और कुछ और समाजिक संगठन जो है वह मिलकर सीजेपी

की भीड़ में आ रहे हैं। लेकि वो जो नीचे भीड़ थी, लाखों की भीड़, वो क्या थी? और आपको क्या लगता है इस देश के छात्र इतने बेवकूफ हैं। किसी पार्टी के एक फोन पर वो लाठी खाने पहुंच जाएंगे। अपना करियर बर्बाद करने पहुंच जाएंगे। आंसू गैस के गोलों के सामने खड़े हो जाएंगे। हफ्ता भर जंतर मंतर पर बैठे रहेंगे। किराए की भीड़ शाम को घर लौट जाती है और जो बनी रहती है ना वह दर्द वाली होती है और दर्द किराए पर नहीं मिलता। बहुत सारे वहां पर अभिभावक थे, बच्चे थे, छोटे-छोटे बच्चे थे। आदमी अपना छोटा बच्चा लेकर क्यों आएगा? राजनीति भीड़ के पीछे तब आती है जब भीड़ पहले से खड़ी हो। अक्सर मुद्दों पर राजनीतिक पार्टियां आग नहीं लगाती। वह आग देखकर हाथ सेकने आती हैं और आग किसने लगाई? उस पेपर लिक ने जिसे खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने माना है। अगर सच में यह मंच केवल राजनीतिक था तो कितना आसान था सरकार के पास इसे खाली करवाना। एक मंत्री जिसकी अगुवाई में कई सारे पेपर लिक हुए हैं, उनको हटा देते। इस देश में पहले भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफे हुए हैं।

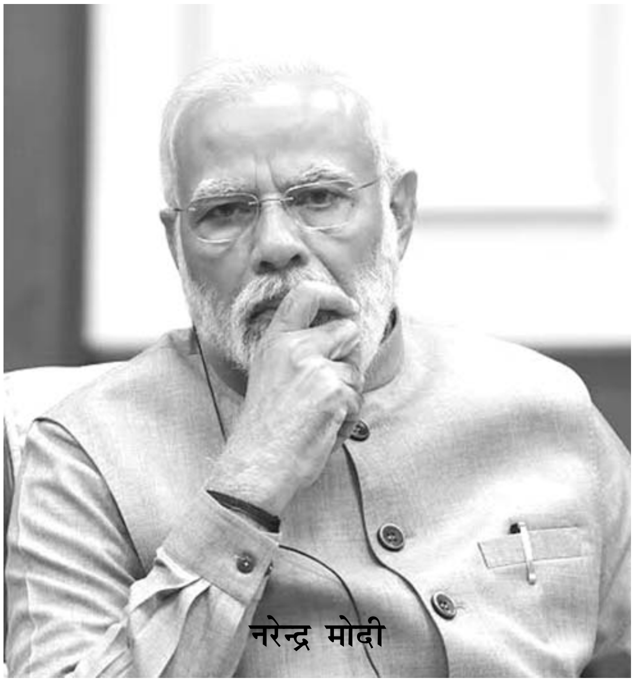
नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब खामोश क्यों रहते हैं हर महत्वपूर्ण विषयों पर? यह सवाल केवल आज NEET को लेकर नहीं है। पिछले दस बारह सालों का पैटर्न है और यह पैटर्न अब देश को परेशान कर रहा है कि मोदी जी चुप क्यों हैं? आप याद कीजिए मणिपुर। महीनों जला। लंबा दौरा नहीं, लंबा संबोधन नहीं। कोविड में आपको थाली बजाने का सीन याद होगा। लेकिन कोविड में जब दूसरी लहर आई थी, भाषण आए थे। ऑक्सीजन के सीधे सवाल पर सीधा जवाब कभी नहीं आया। किसान आंदोलन। साल भर वो सीमा पर बैठे रहे। ऊपर से सीधी बातचीत महीनों बाद की गई। अग्निपथ, जब नौजवान सड़कों पर उतरे। मंत्री बोले। प्रधानमंत्री नहीं आए। संसद में विपक्ष ने एक अंबानी-अडानी को लेकर बार बार सवाल पूछा। प्रधानमंत्री जी ने कई बार जवाब दिए, लेकिन उन नामों पर एक शब्द नहीं लिया, पेपर लीक। यह तो अब एक रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हो गया है। हर बार मंत्री, हर बार एजेंसी लेकिन प्रधानमंत्री कभी नहीं।

जिस जंतर मंतर पर यह हंगामा हो रहा था, इसी जंतर मंतर पर 2023 में देश की बेटियां जो ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहलवान थी, वो महीनों बैठी थी। जब वो लड़कियां मेडल जीतकर आई थीं तो ट्वीट हुए थे, फोटो खिंचाई गई थी, घर बुलाया गया था और हर बार होता है। कोई भी क्रिकेट टीम जीतकर आती है, मोदी जी घर बुलाते हैं। लेकिन जब वो बेटियां इंसाफ मांगने सड़क पर बैठीं तो चुप्पी। और सबसे दुखद बात है कि जिस दिन नई संसद का उद्घाटन हो रहा था, उन बेटियों को सड़क पर घसीटा गया। हर बार एक परसेप्शन डाल दिया जाता है कि यह विपक्ष के लोग हैं, इनका ऐजेंडा है। नई संसद जिसकी ऊंची दीवारें उस दिन भी ऊंची थी जब महिला पहलवानों को घसीटा गया था, आज बस दिखाई पड़ी हैं। कुल मिलाकर कहें तो पैटर्न बड़ा साफ है कि जहां तालियां हैं, वहां पर माइक जाता है। लेकिन जब सवाल आते हैं तो वहां खामोशी आ जाती है। लोकतंत्र की पहली शर्त संवाद है। जब सरकार संवाद छोड़ देती है, तब लोकतांत्रिक संघर्ष अनिवार्य हो जाता है। आसान भाषा में अगर कहें और मेंल समझाने के लिए। तो जब सरकारें सुनना बंद कर देती हैं तो सड़क पर शोर आता है। आज जंतर मंतर के बाद सड़क से लेकर संसद तक जो कुछ दिखा वह इसलिए दिखा क्योंकि सरकार ने संवाद करना छोड़ दिया था और सरकार को यह समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र में सरकारें टियर गैस से नहीं संवाद से चलती हैं। अगर सरकार यह सोचती है कि जनता ने आपको वोट देकर सत्ता की शीर्ष कुर्सी पर पहुंचा दिया और यह पांच साल का ब्लैंक चेक है तो आपकी सोच गलत है। मोदी जी हमेशा थे कि हम जनता के चौकीदार हैं, तो चौकीदार की जवाबदेही तो होती है मोदी जी। जनता सिर्फ वोट लेने के लिए थोड़ी है। वोट के बदले जवाबदेही। 22 लाख बच्चे थे। 10 से ज्यादा मौत हो गई है। सड़क से लेकर संसद तक हंगामा है। बच्चा से लेकर पुलिस वाला तक पीटा है। कहते हैं, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इंदिरा गांधी को भी घमंड था। इतिहास में आप तुलना करते हैं नेहरू जी से, इंदिरा जी से। इतिहास की सिर्फ अच्छी घटनाओं से तुलना नहीं की जाती। इतिहास में जाकर वो भी देखिए आप। क्योंकि चोरी मुफ्त नहीं होती। उसकी कीमत अफवाह

होती है और भरोसा चुकाता है देश।

गौरतलब है कि दिल्ली के जंतर पर NEET पेपर लिक को लेकर पहले से जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, अपनी मांगे शांतिपूर्ण ढ़ंग से मांग रहे थे, उसे हाइजेक करके उपद्रवी रंग दे दिया गया। सवाल है कि क्या जंतर मंतर पर कॉकरोच के प्रोटेस्ट ने छात्रों के आंदोलन को कमजोर कर दिया? मतलब यह सवाल इसलिए आ रहा है क्योंकि प्रोटेस्ट को देखने के बाद यह समझ में नहीं आ रहा कि जंतर मंतर पर हो क्या रहा था? यह छात्र आंदोलन था, राजनीतिक रैली थी या कुछ और? मतलब अगर आपने वहां का कार्यक्रम नहीं देखा और आपको सिर्फ फोटो विडियो दिखाया जाए तो समझ नहीं पाएंगे, बता नहीं पाएंगे कि यह NEET और CBSE के नाम पर छात्रों को बुलाया गया प्रदर्शन था। कभी ढपली वाला प्रोटेस्ट देखकर लग रहा था कि जेएनयू का रेगुलर प्रोटेस्ट है। कहीं पर राजनीतिक लोग नजर आ रहे थे, कहीं गरीब किसान नजर आ रहे थे। कुछ आंदोलनजीवी यहां नजर आ रहे थे। प्रोटेस्ट में आजादी, आजादी चल रहा था। कोई उमर खालिद का जिक्र कर रहा था। मंच पर जो अमेरिका से यहां आए थे वो जय भीम, जय भीम, जय भीम कह रहे थे। कॉकरोच पार्टी के प्रवक्ता अपने पीछे बुर्जुग से पंखा हिलवा रहे थे और बैठकर कॉफी पी रहे थे। गर्मी में सांस नहीं ले पा रहे थे। अमेरिका वाले भैया भी दो चार घंटा बैठकर सीधे ए. सी. गाड़ी में बैठ गए। फिर आरएसएस मुर्दाबाद चल रहा था। कोई बुद्धिजीवी आए वो समझाने लगे कि इवीएम को हैक किया जा सकता है। एक आदमी लाल डायरी लेकर आ गया जो कह रहा है कि यह संविधान है, खोलो। लाल डायरी के अंदर उनकी अपनी शेरो शायरी लिखी पड़ी थी। 22 मिलियन फॉलोवर लेकर जिस कॉकरोच मुवमेंट ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था। वह शिक्षा मंत्री जिनकी अगुवाई में इस देश में कितने ऐसे शिक्षा को लेकर कुव्यवस्थाएं हुई, उनके इस्तीफे की मांग को लेकर एक बड़ा जनाक्रोश दिखा, बड़ी हैरानी हुई कि उन धर्मेंद्र प्रधान का नाम यहां आए लोगों को पता नहीं था। आधे लोग कह रहे थे अमित प्रधान का इस्तीफा लेने आए हैं। धर्मेन्द्र प्रधान और सरकार वाले हंस रहे होंगे कि हमारी सारी मुसीबत इन लोगों ने खत्म कर दी। मतलब NEET और CBSE के छात्रों के सवाल इतने जायज थे, उनका दर्द इतना जायज था उसको तमाशा बना दिया गया। क्योंकि इनके नाम पर मंच सजाया गया और सच कहें तो मंच पर छात्र के सिवा सब था। जिस मंच से पेपर लिक, परीक्षा व्यवस्था और जवाबदेही पर सवाल उठाना चाहिए था। जहां पर छात्रों को आगे करके,

उनके मां बाप को आगे करके मंच से कहना चाहिए था कि लाखों छात्र और उनके परिवार महीनों नहीं सालों साल मेहनत करते हैं कि निष्पक्ष परीक्षा हो। क्या इस देश में उन्हें निष्पक्ष परीक्षा नहीं मिल सकती? वहां पर जय भीम, आरएसएस मुर्दाबाद, उमर खालिद, हमें चाहिए आजादी..। मतलब क्या यह आंदोलन छात्रों की आवाज को मजबूत करने के लिए था या छात्रों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए? जिस आंदोलन को उनकी आवाज बनना था, वह कुछ लोगों के दिखावे तक सीमित रह गया। छात्रों के नाम पर दुकान सजाई गई थी। इन चेहरों को देखकर सरकार को मौका मिल जाता है यह कहने का कि देखो, इनकी वजह से परीक्षा व्यवस्था का सच में शोर दब गया। प्रेस कांफ्रेंस में जो लड़का चार घंटा बैठ कर ज्ञान दे रहा था, वो लोग जो सरकार को हिलाने की बात कर रहे थे, चार घंटा धूप में खड़े नहीं हो पाए। सच कहें तो जंतर मंतर पर राजनीतिक कार्यकर्ता थे, कैमरे थे, पुलिस वाले थे, नारे थे, भाषण थे। सबके पास बोलने के लिए कुछ ना कुछ था। लेकिन वो लड़का जिसने सालों साल मेहनत करके NEET की तैयारी की थी, CBSE की तैयारी कर रहा है उसकी कहानी कहीं नहीं थी। वो लड़की जिसने जवानी टेस्ट सिरीज और किताबों में निकाल दी, उसकी आवाज नहीं थी। वो पिता जिसने कोचिंग फी भरने के लिए कर्जा लिया था, पेपर कैंसिल हो गया, अब कहां से पैसा लाएगा, उसकी बारे में कोई बात नहीं थी। वो मां जो दुआ कर रही है, प्रार्थना कर रही है कि परीक्षा हो जाए, लड़का तैयार बैठा है। भगवान ईमानदारी से परीक्षा करा दो, लड़का निकल जाएगा। उसका दर्द नहीं था और ना वो बच्चा वहां दिख रहा था। क्या छात्र आंदोलन, छात्रों की समस्या, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, यह सारे मसले जो थे, शिक्षा व्यवस्था में जो कुव्यवस्थाएं हैं, पेपर ईमानदारी से हो। यह सारे मसले गायब हो गए।

बहरहाल, सीजेपी के इस

आंदोलन का नेतृत्व मिलने के बाद दिल्ली का जंतर मंतर रणक्षेत्र बन गया। सीजेपी द्वारा आयोजित प्रदर्शन के दौरान अचानक स्थिति उस वक्त बेकाबू हो गई, जब प्रदर्शनकारी संसद मार्ग की ओर बढ़ने की कोशिश करने लगे। पुलिस की कड़ी घेराबंदी और वॉटर कैनन की गाड़ियों की तैनाती के बावजूद माहौल देखते ही देखते तनावपूर्ण हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों और ग्राउंड रिपोर्टर्स के मुताबिक, सुबह 10 बजे तक प्रदर्शन बिल्कुल शांतिपूर्ण चल रहा था। प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लेकर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन दोपहर में माहौल तब बदला जब कुछ युवा कार्यकर्ताओं के समूह ने पुलिस द्वारा लगाए गए दूसरे स्तर के बैरिकेड्स को पार करने का प्रयास किया।

स्थिति को हाथ से निकलता देख दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने तुरंत मोर्चा संभाला। पुलिस द्वारा रोके जाने पर कार्यकर्ताओं और सुरक्षाबलों के बीच तीखी झड़प हुई, जिसके बाद कई प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया और जंतर-मंतर और आसपास के पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के बीच सपा नेता डिंपल यादव, इकरा हसन और प्रिया सरोज समेत सभी सपा सांसदों के साथ संसद से जंतर मंतर की ओर निकल पड़ीं। सभी उनके हाथ में पोस्टर थे, जिन पर लिखा था 'नीट है या चिट है'। कई सांसदों के हाथ में 'पेपर लिक' वाले पोस्टर्स भी दिखाई दे रहे थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारी सांसदों को हिरासत में ले लिया। डिंपल यादव ने सोनम वांगचुक और छात्र आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने सरकार से छात्रों की मांगों पर संवाद शुरू करने और परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की। मार्च के दौरान डिंपल यादव ने कहा कि देश के युवा अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन सरकार उनकी बात सुनने और संवाद करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक भी लगातार सरकार से बातचीत की अपील कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। उनके मुताबिक, मौजूदा व्यवस्था से सबसे ज्यादा नुकसान छात्रों और युवाओं को हो रहा है, जिससे उन पर मानसिक दबाव बढ़ रहा है। छात्र बस निष्पक्ष परीक्षा चाहते हैं। बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च को लेकर दिल्ली सड़क से संसद तक बवाल मचा। कई स्थानों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों पर झड़प की देखने को मिली। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें पुलिस लाठीचार्ज करती दिखाई दे रही है। जंतर मंतर के इस वीडियो में युवक

चिल्लाते हुए कहता है कि 'मारो मुझे मारो और मारो'। धारा 163 का उल्लंघन कर रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने में फिलहाल पुलिस ज्यादा सफल नहीं रही है। जंतर मंतर पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान प्रदर्शनकारियों को करने के लिए लाठियां भांजते नजर आए। जंतर मंतर से निकले कुछ प्रदर्शनकारी संसद भवन के पास पहुंच गए। इन्हें रोकने के लिए भी पुलिस ने आंसूगैस के गोले दागे।

छात्र आन्दोलन का दूसरा हिंसक प्रदर्शन जंतर मंतर के बाद बिहार की राजधानी पटना की सड़कों एवं अन्य जिलों में भी देखने को मिला। 22 जुलाई को 6 घंटे तक पटना की सड़कें युद्ध क्षेत्र बना रहा। इस हिंसक प्रदर्शन में छात्र आन्दोलन का अलग ही रूप देखने को मिला। गांधी मैदान से शुरू हुआ राजभवन मार्च दिनभर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच शक्ति प्रदर्शन का केंद्र बना रहा। छात्रों की रणनीति और अचानक बढ़ते हुजूम के आगे पुलिस प्रशासन बेबस नजर आया। हुआ यह कि पुलिस जैसे ही प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगा रही थी। उसे भीड़ उठाकर अपने साथ ले जा रहे थे। बैरिकेडिंग हटने के बाद प्रदर्शन में शामिल लोग एक साथ आगे की ओर बढ़ रहे थे, जिसे पुलिस रोक नहीं पा रही थी। प्रदर्शनकारियों ने अलग-अलग रास्तों से आगे बढ़कर

पुलिस बल को लगभग छह घंटे तक छकाया। इस दौरान राजधानी का डाकबंगला चौराहा, जेपी गोलंबर, सीएम हाउस और बेली रोड अंडरपास युद्ध के मैदान में तब्दील हो गए। सुबह करीब 10.30 बजे छात्रों ने गांधी मैदान के गेट नंबर 12 को तोड़ते हुए राजभवन के लिए अपना मार्च शुरू किया। पुलिस ने सबसे पहले 11 बजे जेपी गोलंबर पर बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने की कोशिश की। यहां पुलिस द्वारा लाठीचार्ज, वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़े जाने के बावजूद छात्र पीछे नहीं हटे और बैरिकेडिंग तोड़कर डाकबंगला चौराहे की ओर बढ़ गए। डाकबंगला चौराहे पर हजारों की संख्या में पहुंचे छात्रों ने करीब एक घंटे तक सरकार के खिलाफ उग्र नारेबाजी की। इसके बाद छात्र सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए राजभवन और सीएम हाउस की दिशा में निकल गए। मुख्यमंत्री आवास और राजभवन के समीप पहुंचे प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज करते हुए उन्हें खदेड़-खदेड़ कर पीटा। इस दौरान कई छात्र विरोध जताते हुए सड़क पर लेट गए, जिन्हें पुलिस घसीटकर गाड़ियों में लादती दिखी। पुलिस की इस कार्रवाई में कई छात्र-छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बावजूद छात्रों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वे दोबारा संगठित होकर डाकबंगला चौराहे पर जुट गए। प्रदर्शन के उग्र होने के साथ ही डाकबंगला और बेली रोड इलाके में जमकर पथराव हुआ। प्रदर्शनकारियों ने पटना आइजी की एस्कार्ट गाड़ी, सिटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार की गाड़ी और कई थाना पुलिस के वाहनों में तोड़फोड़ की। हमले में भागलपुर से भाजपा विधायक रोहित पांडे की गाड़ी को पलटने का प्रयास किया गया। उनके साथ मारपीट की गई, जिससे वे घायल हो गए। इसके अलावा भाजपा विधायक विनय बिहारी और पार्टी

नेता अजय सिंह की गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए गए। पथराव की चपेट में आने से आइजी जितेंद्र राणा, एसएसपी कार्तिकेय शर्मा, एसडीएम कृतिका मिश्रा, टाउन डीएसपी-2 कामाख्या नारायण प्रसाद, और गांधी मैदान थानाध्यक्ष समेत 17 से अधिक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि 20 से अधिक अन्य को चोटें आई हैं। पथराव और लाठीचार्ज में घायल 37 छात्र-छात्राओं को पुलिसकर्मियों ने उपचार के लिए पीएमसीएच, आइजीआइएमएस, एलएनजेपी और गार्डिनर रोड अस्पताल में भर्ती कराया। शाम लगभग पांच बजे पुलिस ने हड़ताली मोड़ और डाकबंगला के पास अंतिम बार लाठीचार्ज कर और आंसू गैस के गोले दागकर भीड़ को पूरी तरह खदेड़ा। पटना आइजी जितेंद्र राणा के आदेश पर दर्जनों छात्रों को हिरासत में लेकर बसों से थाने भेजा गया है। बता दें कि बिहार में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर छात्रों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। छात्रों के प्रदर्शन के दौरान भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को अलग-अलग स्थानों पर लाठीचार्ज से लेकर हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। वही राज्य के विभिन्न जिलों में छात्रों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए 1975 के छात्र आंदोलन की याद फिर से ताजा हो गई है। क्या बिहार के युवा फिर से एक बड़े आंदोलन की राह पर चल पड़े हैं। बिहार के जहानाबाद, दरभंगा, कटिहार, बेगूसराय तथा अन्य जिलों में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और सरकारी प्रतिष्ठानों पर कथित तौर पथराव किया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। अधिकारियों के अनुसार, जहानाबाद में बड़ी संख्या में छात्रों ने कारगिल चौक से काको मोड़ तक विरोध मार्च निकाला। इस दौरान प्रदर्शनकारी कथित तौर पर उग्र हो गए और पुलिस द्वारा लगाए गए अवरोधकों को तोड़ने का प्रयास किया। जहानाबाद के पुलिस अधीक्षक (एसपी) कोटा किरण कुमार ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के उग्र हो जाने के कारण पुलिस को स्थिति के अनुरूप 20 से 30 राउंड हवाई फायरिंग करनी पड़ी। नगर थाना प्रभारी तथा कुछ अन्य पुलिस अधिकारी भी घायल हुए। दरभंगा के लोहिया चौक पर प्रश्नपत्र लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों के पथराव में सिटी एसपी और एक कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि करीब एक दर्जन पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें आईं। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस को स्थिति को संभालने के लिए हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान कई राहगीर भी घायल हुए। घटना की पुष्टि करते हुए दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने कहा कि प्रदर्शन के आयोजकों की पहचान करने के प्रयास किये जा रहे हैं। कुमार ने बताया कि पांच लोगों को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद थे। कटिहार में नीट प्रश्नपत्र लीक मामले के विरोध में सैकड़ों छात्रों ने जिलाधिकारी कार्यालय परिसर के सामने प्रदर्शन किया और सुरक्षाकर्मियों पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने

प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा नीत केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। कटिहार के जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने संवाददाताओं से कहा कि हर व्यक्ति को संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हिंसा में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। बेगूसराय में प्रदर्शनकारियों की भीड़ बढ़ने के साथ ही स्थिति उग्र हो गई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। पुलिस के अनुसार, कुछ प्रदर्शनकारियों ने जवाब में पथराव किया, जिससे कई पुलिसकर्मी और कई छात्र घायल हो गए। मुंगेर और मुजफ्फरपुर सहित अन्य जिलों से भी कथित नीट प्रश्नपत्र लीक के विरोध में विरोध-प्रदर्शन की खबरें मिली हैं। इन जिलों में प्रदर्शन एक दिन पहले राज्य की राजधानी पटना में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद हुए, जहां प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी। पटना में भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करने के साथ आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े थे। इसके साथ ही देश भर में नीट पेपर लीक के खिलाफ हुए छात्रों के प्रदर्शन के दौरान बिहार का सिवान जिला चर्चा में रहा। 25 जुलाई को सिवान में प्रदर्शन के दौरान एके 47 राइफल का इस्तेमाल हुआ था। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एके 47 के इस्तेमाल को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से लेकर बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया था। तेजस्वी यादव ने कहा कि सम्राट सरकार बिहार को 'पुलिस स्टेट' बना रही है, वहीं राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया था, 'दिल्ली में पैलेट गन और बिहार में एके 47 । पूरा सिस्टम स्टूडेंट्स के खिलाफ जानलेवा है।

वही दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए हिंसक प्रदर्शन पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि आज लोकतंत्र के इतिहास में ये

काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पुलिस की आंखों में भी शर्मिंदगी दिख रही थी। कुछ पुलिसकर्मी गुंडे बने हुए थे। कुछ पुलिसवाले बिना वर्दी के आए और बच्चों को मारा। बच्चों को करंट दिया। जहां नियम होता है कि आपको पैरों पर मारना है, वहां बच्चों के सीने पर मारा है, ये आघात भारत माता के सीने पर किया है। हमारी मांग है कि शिक्षा मंत्री को हटाएं, सरकार जिम्मेदारी ले। इतनी अहंकारी कठोर और निर्दयी सरकार शायद ही देश के इतिहास ने देखी हो। सपा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि दिल्ली में छात्रों की आवाज उठा रहीं लोकसभा सांसद डिंपल यादव एवं अन्य सपा सांसदों को पुलिस द्वारा डिटेन किया जाना, साथ ही छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाना बेहद निंदनीय एवं अलोकतांत्रिक है। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे सांसदों को पुलिस स्टेशन में रखा गया, जबकि बाहर बच्चों को पीटा जा रहा है। यह कैसी सरकार है? आप बच्चों की बात नहीं सुनना चाहते। अगर NEET परीक्षा हुई और उसमें गड़बड़ी हुई, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? उन्होंने कहा कि आप 'विश्वगुरु' बनना चाहते हैं; आप दावा करते हैं कि दुनिया 'अमृत काल' में है, फिर भी आप अपने मंत्रियों को नहीं हटा सकते। आपने नौकरियां या रोजगार नहीं दिया। अगर नौकरियां दी गई होतीं, तो क्या बच्चे सड़कों पर उतरते? अभी मुख्य सवाल यह है कि NEET छात्रों को न्याय मिलना चाहिए और यहां विरोध कर रहे छात्रों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। जब लोग विरोध प्रदर्शन करते थे, तो अंग्रेज भी उनकी बात सुनते थे। इसीलिए आज पूरी दुनिया में गांधी का सम्मान किया जाता है। उन्होंने विरोध का रास्ता दिखाया। जिस तरह से वे प्रदर्शनकारियों को हटा रहे हैं। उम्मीद है कि सरकार को अंत में 'सम्मानजनक विदाई' न मिल जाए।

वही इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा

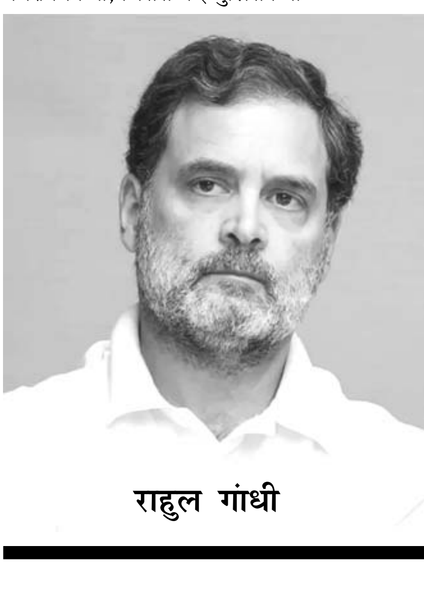

राहुल गांधी

तेजस्वी यादव

डिंपल यादव

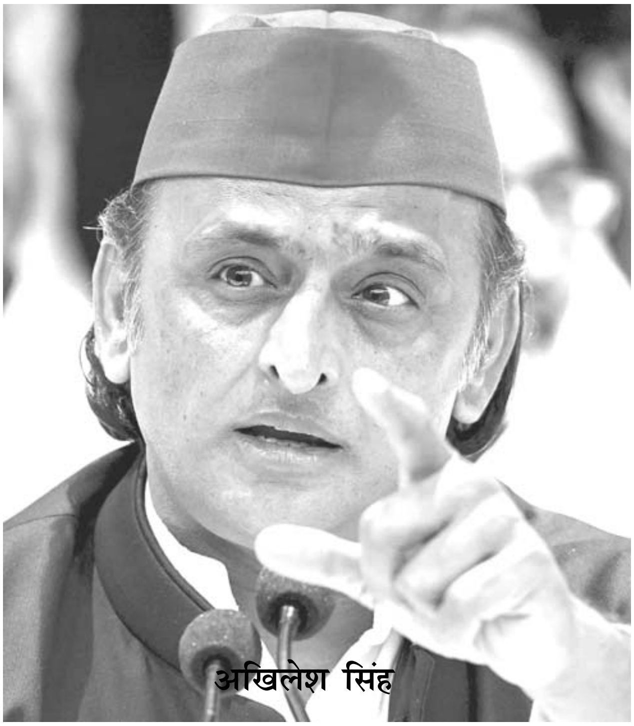

कि देश में शिक्षा नीति को लेकर गंभीर सवाल हैं, लेकिन सरकार चर्चा करने के बजाय छात्रों पर बल प्रयोग कर रही है। प्रियंका गांधी ने कहा, 'हम सभी शिक्षा नीति पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। इसमें कई गंभीर समस्याएं हैं, लेकिन सरकार बातचीत करने के बजाय छात्रों पर आंसू गैस छोड़ रही है और उनकी पिटाई कर रही है। आखिर क्यों? ये हमारे ही बच्चे हैं।'

ज्ञात हो कि दिल्ली में छात्रों के संसद मार्च की शुरुआत परीक्षा में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक और भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की मांग से हुई थी। लेकिन समय के साथ यह प्रदर्शन केवल शिक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं रहा। प्रदर्शन में शामिल कई छात्र इसे सरकारी जवाबदेही, संस्थागत भरोसे और युवाओं के भविष्य से जुड़े व्यापक सवालों से जोड़कर देख रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत में नागरिकता कानून, किसान आंदोलन और महिला पहलवानों के प्रदर्शन जैसे कई बड़े आंदोलन हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि मौजूदा छात्र आंदोलन को अलग क्यों माना जा रहा है? मुद्दा केवल शिक्षा मंत्री तक सीमित नहीं रहा। शुरुआत में प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी तय करने और इस्तीफे की मांग कर रहे थे। लेकिन अब प्रदर्शन में शामिल कई छात्र सरकार की समग्र शिक्षा नीति और परीक्षा प्रणाली को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भी सवाल उठा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग मानता है कि जब किसी मंत्री का सार्वजनिक रूप से बचाव किया जाता है, तो उस विभाग से जुड़े विवाद केवल मंत्रालय तक सीमित नहीं रहते बल्कि सरकार की व्यापक राजनीतिक जवाबदेही का हिस्सा बन जाते हैं। वहीं सरकार का कहना रहा है कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कई कदम उठाए गए हैं और अनियमितताओं पर कार्रवाई की जा रही है। इस आंदोलन की एक खास बात यह भी है कि इसका संचालन किसी एक राजनीतिक दल, छात्र संगठन या प्रमुख चेहरे तक सीमित दिखाई नहीं देता। सोशल मीडिया के जरिए अलग-अलग शहरों के छात्र एक-दूसरे से जुड़े और विरोध प्रदर्शनों का समन्वय करते दिखे। ऐसे विकेंद्रीकृत आंदोलनों को पारंपरिक राजनीतिक ढांचे से अलग माना जाता है क्योंकि इनमें निर्णय लेने का केंद्र स्पष्ट नहीं होता। वही प्रदर्शन का मुख्य फोकस परीक्षा प्रणाली, रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दों पर रहा है। ये ऐसे विषय हैं जिनका असर अलग-अलग राज्यों, जातियों और सामाजिक समूहों के युवाओं पर पड़ता है। इसी वजह से आंदोलन को किसी एक पहचान आधारित राजनीति के दायरे में रखना अपेक्षाकृत कठिन माना जा रहा है। हालांकि सरकार समर्थक कुछ समूहों ने आंदोलन की मंशा और राजनीतिक पृष्ठभूमि पर सवाल भी उठाए हैं। प्रदर्शन में शामिल कई छात्रों का कहना है कि उन्हें अदालतों, जांच एजेंसियों और अन्य संस्थागत प्रक्रियाओं से अपेक्षित राहत नहीं मिली। इसी वजह से उन्होंने सार्वजनिक विरोध को अपनी बात रखने का प्रभावी माध्यम माना। हालांकि न्यायपालिका और अन्य संस्थाएं समय-समय पर ऐसे मामलों में सुनवाई और हस्तक्षेप करती रही हैं।

इसलिए यह धारणा सभी पक्षों द्वारा समान रूप से स्वीकार नहीं की जाती। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांग यह रही है कि बार-बार सामने आने वाले पेपर लीक और भर्ती संबंधी विवादों के लिए स्पष्ट जिम्मेदारी तय की जाए। वहीं विश्लेषकों का कहना है कि यह आंदोलन केवल किसी एक परीक्षा या भर्ती प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी संस्थानों की विश्वसनीयता और युवाओं के भविष्य से जुड़े व्यापक सवाल उठा रहा है। सरकार की ओर से अब तक प्रशासनिक कदम, जांच और कुछ मामलों में कार्रवाई की जानकारी दी गई है। दूसरी ओर प्रदर्शनकारी इसे अपर्याप्त बताते हुए लगातार विरोध जारी रखे हुए हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार सरकार के सामने चुनौती केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने की नहीं, बल्कि युवाओं के बीच भरोसा कायम रखने की भी है। आने वाले समय में सरकार बातचीत, नीति सुधार या प्रशासनिक कार्रवाई-किस रास्ते को प्राथमिकता देती है, इस पर भी नजर रहेगी। इस आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू शायद इसका सामाजिक और पीढ़ीगत स्वरूप है। बड़ी संख्या में ऐसे छात्र इसमें शामिल हैं जो पहली बार किसी सार्वजनिक आंदोलन का हिस्सा बने हैं। दुनिया के कई देशों में हाल के वर्षों में छात्रों और युवाओं ने जलवायु परिवर्तन, आर्थिक संकट, शिक्षा और लोकतांत्रिक अधिकारों जैसे मुद्दों पर बड़े आंदोलनों का नेतृत्व किया है। भारत में भी कुछ विश्लेषक इस प्रदर्शन को उसी व्यापक वैश्विक प्रवृत्ति के संदर्भ में देख रहे हैं, हालांकि इसकी दिशा और राजनीतिक प्रभाव का आंकलन अभी जल्दबाजी होगा। दिल्ली का यह छात्र आंदोलन फिलहाल केवल परीक्षा प्रणाली के विरोध तक सीमित नहीं दिखाई देता। यह युवाओं की आकांक्षाओं, रोजगार, शिक्षा और सरकारी जवाबदेही से जुड़े व्यापक प्रश्नों को सामने ला रहा है। हालांकि यह कहना अभी जल्द होगा कि इसका दीर्घकालिक राजनीतिक असर क्या होगा। लेकिन इतना स्पष्ट है कि इस आंदोलन ने युवाओं की चिंताओं और सार्वजनिक संस्थानों में भरोसे के सवाल को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया है। आने वाले समय में सरकार की प्रतिक्रिया और आंदोलन की दिशा, दोनों ही इसके महत्व को तय करेंगे।

गौरतलब है कि जंतर-मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे धरने पर बैठे। कांग्रेस नेताओं ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। सभी ने खरगे के घर से पीएम आवास तक पैदल मार्च किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी धरना स्थल पर पहुंचे। कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। प्रदर्शन कर रहे कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया। इनमें पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी शामिल है। केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने राहुल गांधी से बात की। कांग्रेस के कई नेता दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के पास दोपहर करीब साढ़े 3 बजे से धरने पर बैठे। कांग्रेस का यह प्रदर्शन बेहद सीक्रेट रहा। सरकार को इसकी भनक तक नहीं लगी। जब ये लोग 100 मीटर दूर थे तब मीडिया को जानकारी दी गई। इधर, कांग्रेस के प्रदर्शनकारी नेताओं से बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पहुंचे। राहुल गांधी से चर्चा करने के बाद वे गृह मंत्री अमित शाह के पास गए। शाह से बातचीत के बाद फिर धरनास्थल पहुंचे हैं। हिरासत में लिए जाने पर पंजाब कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि यह बीजेपी का आतंकवाद है। वे छात्रों की बात नहीं सुनते। कांग्रेस प्रमुख खरगे ने कहा कि जंतर-मंतर पर किए गए बल प्रयोग का सरकार को जवाब देना होगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल, पवन खेड़ा और अन्य कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि हमारी एक सीधी-सी मांग है। हमारे विपक्ष के नेताओं ने लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों में यह मांग उठाई है। मांग यह है कि गृह मंत्री संसद में इस पर स्पष्टीकरण दें और सदन में इस मुद्दे पर चर्चा हो। हम चाहते हैं कि वे इस बात पर बयान दें कि किस तरह लोकतंत्र और हमारे संविधान की हत्या की जा रही है और छात्रों पर अत्याचार हो रहे हैं। हम 45 दिनों से शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधते हुए युवाओं के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'भारत के इतिहास के सबसे युवा-विरोधी प्रधानमंत्री' हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कथित रूप से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ कार्रवाई करने में भी असफल रही है। वही राहुल गांधी ने दावा किया कि देश में 152 पेपर लीक की घटनाएं हुई, जिनसे करीब 7.5 करोड़ छात्र प्रभावित हुए, लेकिन किसी भी दोषी को सजा नहीं मिली। उन्होंने कहा कि इसकी सबसे बड़ी कीमत मेहनत करने वाले छात्रों को चुकानी पड़ी है। उन्होंने लिखा कि पेपर लीक करने वाले लोग खुले घूम रहे हैं, जबकि अपने अधिकारों और शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाने वाले छात्रों को विरोध प्रदर्शन के दौरान कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि जब छात्रों ने शिक्षा व्यवस्था से जुड़े सवाल उठाए तो उन्हें जवाब के तौर पर 'लाठी और हिरासत' मिली। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं की समस्याओं का समाधान करने के बजाय उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि यह सरकार केवल युवाओं की उम्मीदों को पूरा करने में असफल नहीं हो रही, बल्कि उन पर दबाव भी बना रही है। उन्होंने युवाओं से जुड़े मुद्दों पर सरकार की नीतियों की आलोचना की। हालांकि, केंद्र सरकार पहले भी पेपर लीक

और परीक्षा सुधारों को लेकर कई कदम उठाने का दावा कर चुकी है। सरकार का कहना है कि परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सख्त नियम लागू किए गए हैं। वही पेपर लीक विवाद पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर छात्रों के साथ कायरता और क्रूरता से पेश आने का आरोप लगाया। उन्होंने सरकार से पुलिस कार्रवाई रोकने और संवाद शुरू करने की अपील की। सोनिया गांधी ने समाचार पत्र हिंदू में लिखे अपने आलेख में कहा कि देश भर में परीक्षा पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में आ रही गिरावट के खिलाफ छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांगें बहुत स्पष्ट हैं, सरकार अपनी जवाबदेही तय करे और शिक्षा में सुधार लाए। 20 जुलाई 2026 का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को दबाने के लिए लाठीचार्ज, आंसू गैस और पैलेट गन का हिंसक इस्तेमाल किया। इस हिंसा में कई निर्दोष छात्र घायल हुए। गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि पैलेट के इस्तेमाल को जरूर उनकी मंजूरी मिली होगी। उन्होंने कहा इस सरकार में हिंसा की यह पहली घटना नहीं है। 2020 में सीएए-एनआरसी प्रदर्शनों के दौरान भी पुलिस यूनिवर्सिटी कैंपस में घुसी थी और महिला पहलवानों के साथ भी बदसलूकी की गई थी।

बहरहाल, आधी रात को देश के प्रधानमंत्री पहली बार शायद अपने फोन से वीडियो बना रहे थे। प्रधानमंत्री मित्रों कहकर सम्बोधित करते है, वो जेन जी को फ्रेंस कह कर सम्बोधित कर रहे थे। फ्रेंस इंस्टाग्राम के फॉर्मेट में वीडियो बना रहे थे। ताकि रील पर वायरल हो, शॉर्ट्स में वायरल हो, लोग जानें। उन्होंने फास्ट कोर्ट का ऐलान किया, शिक्षा की सेक्रटरी को हटा दिया। जो बच्चे इस दुनिया में नहीं, उनके लिए मुआवजे का ऐलान किया और यह भी कहा कि हम इसको लेकर बहुत सीरियस है। और ये लड़ाई आगे चलेगी बहुत कड़ी सजा देंगे। अब जनता के मन में सवाल है। ये भीड़ को देख कर मोदी जी का डर है या मोदी जी को फाइनली रिलाइज हुआ कि बच्चों की जो प्रॉब्लम है वो बहुत जेनविन है। एक इम्पोर्टेंट सवाल ये भी कि क्या सोनम वांगचुक के जाने से धरना खत्म होगा या ये प्रोटेस्ट सोनम वांगचुक से आगे निकल चुका है। क्योंकि सोनम के आने के पहले से यह प्रोटेस्ट था। ये अलग बात है की मीम से आंदोलन बने। कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रोटेस्ट को सोनम वांगचुक ने ही बड़ा किया। सोनम वांगचुक के आने से क्रेडिबिलिटी बढ़ी। लेकिन फिर भी अगर सोनम के आये बगैर ये शुरू हो सकता है तो क्या सोनम के जाने के बाद ये हट जाएगा और आखिरी सवाल की इस देश में आज तक कोई भी आंदोलन किसी मंत्री कुर्सी हिला नहीं पाया है। क्या इतिहास इस बार भी खुद को दोहरा रहा है। सारी मांगे मान ली गयी। ये वो सवाल हैं जो जंतर मंतर से लेकर देश के सारे घरों में फिलहाल चल रहा है। सरकार ने जब कहा की दोपहर में छात्रों से बातचीत की जाएगी और उसके बाद अब बच्चों की जीत हो गयी तो ये सवाल की क्या ये आंदोलन का दी एंड है या फिर इंटरवेल भी नहीं हुआ। आधी रात को प्रधानमंत्री

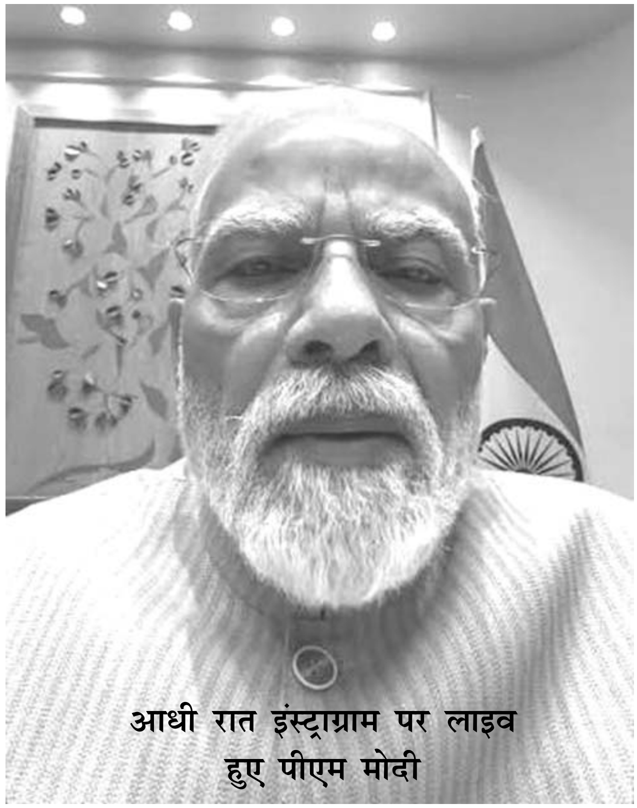

आधी रात इंस्ट्राग्राम पर लाइव हुए पीएम मोदी

का आना बताता है कि इस मामले को लेकर सरकार परेशान हुई है। इसको लेकर वो सीरियस है वो इसे खत्म करना चाहती है। सोनम वांचुक मान जाते हैं हैप्पी तस्वीरें आती है, एक मेसेजिंग दी जा रही है। सरकार की तरफ से सरकार के चाहने वालों की तरफ से बच्चों की मांग हमने मान ली है। सोनम वांगचुक को बना लिया है। अब जो बचे हैं वो वो एलिमेंट है जो हिंसा करवाना चाहते हैं। सोनम वांचो खुद ट्वीट कर रहे है की पीसफुल होना चाहिए इसमें कुछ गए है। सलमान खान से लेकर बहुत सारे बॉलीवुड के सितारे अपील कर रहे हैं की प्रोटेस्ट को एंड कर दिया जाए और अब बच्चे पढ़ाई लिखाई करे घर लौटे। सोना वांगचुक भी एंड करे। और यही ऐसे सवालों के बीच में वो सवाल आ रहा है की क्या इस प्रोटेस्ट का दी एंड हो गया?

क्या सोनम बेवफा निकले या समझदार? वे नीट आंदोलन को लेकर जब सोनम वांगचुक ने 26वें दिन सरकार के मंत्रियों से मिलकर अपने अनशन को खत्म किया तो ये कड़वा सवाल देश के बहुत से लोग सवाल कर रहे थे कि क्या सोनम वांगचुक ने छात्रों के साथ गद्दारी कर दी, बिक गए? सोनम वांगचुक को जो लोग गालियां दे रहे थे आज वो कह रहे है कि क्या महान व्यक्ति है। असली लड़ाई तो यही लड़ रहे थे, चेहरा थे। कह रहे है की बच्चों का हित होगा और जो सोनम वांगचुक के नाम पर दुनिया भर में लोगों को बुला रहे थे वो दबी जुबान में कह रहे की सोनम सर आपने क्या बेवफाई कर दी। आपने सरकार से डील कर ली है। जो आदमी 26 दिन से देश के लिए भूखा बैठा था, जिसके लिए देश दुआएं कर रहा था, अब उसको लेकर बहुत सारे लोग कह रहे की भाई साहब डील किस से पूछ कर ली, क्या बेवफाई कर दी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कॉकरोच शब्द देते हैं। एक आदमी कॉकरोच के नाम से मीम पेज बनाता है, फॉर्म भरवाता है, इंडिया आता है। 4,507 सौ लोग नजर आते हैं। 8 दिन बाद सोनम जैसा चेहरा आता है। अचानक एक बड़ा आंदोलन बन जाता है। देश दुनिया में सबकी निगाहें जाती है, भीड़ बढ़ने जा लगती है। हालत ये

होती है की जनता सड़क से संसद जाने को तैयार हो जाती है, फिर आदमी को ठग लिया आता है। लेकिन 26 दिन बाद यही आदमी अनशन तोड़ता है और ये सवाल उठता है, क्या सोनम बेवफा है? और ये सवाल जंतर मंतर पर भी उठ रहा है। यह सवाल देश भर में भी उठ रहा है। सवाल नंबर एक जो देश के मन में आ रहा है। क्या सोनम ने आंदोलन को आधे रास्ते पर छोड़ दिया, जिस मांग के लिए हजारों बच्चे, धूप में बैठे लाठी खाये, पीटे बरसात में नहाये खाली, पेट आए, देश दुनिया से ट्रैवल कर के यहाँ बैठे रहे, क्या उनकी मांग के बगैर समझौता कर लिया गया? क्या धर्मेंद्र प्रधान को न हटाना सरकार की जीत है, कॉकरोच जनता पार्टी की हार या दूसरा सवाल कहानी उलटी है। सोनम वांगचुक वहाँ बैठे सभी ज्यादा लोगो ऐसे समझदार निकले और सरकार ऐसे छात्रों के हित की सारी बातें बना। ये सुनिश्चित किया की जैसे लद्दाख में 6 लोगों के मरने के बाद एन.एस. लाकर उनको जेल में ठूंस दिया गया था। किसी बच्चे को जेल में नहीं डाला जाएगा। एक बच्चे पर एफआईआर नहीं होगा, उसका करियर खराब नहीं होगा। जिनकी मृत्यु हो गई है उन्हें मुआवजा मिलेगा, शिक्षा, सचिव का इस्तीफा भी करवा दिया। यह भी कह दिया। संसद में मामला उठेगा और यहाँ तक सुनिश्चित किया कि भविष्य में अगर पेपर लीक होता है तो फास्ट ट्रैक में जाएगा। तो क्या सोनम ने आंदोलन को बचा लिया? इन दो सवालों के बीच फिलहाल देश बंटा हुआ है। एक सवाल और भी है कि इस देश में आज तक एक भी आंदोलन नहीं हुआ है, जो ऐसे हुआ, क्या सोनम यह समझ रहे थे? क्या 2011 में अन्ना आंदोलन में अन्ना, हजारे और केजरीवाल में जो हुआ था, वही कहानी सोनम वांगचुक और दीपक में हुई है। सवाल है कि सोनम पर बेवफाई का इलजाम क्यों है। तो सोनम पर बेवफाई का एग्जाम इसलिए लग रहा है क्योंकि सीजेपी का प्रोटेस्ट सोनम वांगचुक के आने के 8 दिन पहले शुरू हुआ था। 20 जून से कुछ बच्चे हैं जो जंतर मंतर पर बैठे थे, लाठी खाए, बरसात में रहे। भूखे पेट भी रहे होंगे। कई सारे बच्चे थे। उन बच्चों की मांग को लेकर जिनका पेपर लीक हुआ था, कई बच्चों की जान भी गई। अब ये मांग जिद्द नहीं थी, दर्द था। लेकिन इसको गंभीरता से लिया नहीं जा रहा था। फिर सोनम वांगचुक का और इस आंदोलन को चेहरा मिल गया। सारे कलाकार, अभिनेता, नेता सब इस मंच पर जाने लगे। ये प्रोटेस बड़ा हो गया। नॉन सीरिज से काफी सीरियस हो गया। लेकिन अब जब अनशन टूटा और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ। क्योंकि पहली शर्त थी बच्चों पर एफआईआर न हो, दूसरी शर्त थी मुआवजा दिया जाए, तीसरा फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाए, संसद में चर्चा हो और आखिरी हो सके तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। उसे लेकर बच्चा सोच रहा है की क्या हमारी लड़ाई का सौदा हुआ और हमें पता नहीं चला और यहीं से सोनम की बेवफाई का सवाल और हम ये स्पष्ट कर दे की जो ये सोच रहे हैं वो गद्दार नहीं है, दुखी होना गद्दार होने में फर्क होता है। सोनम को डर लग रहा है कि आंदोलन में हिंसक लोग आ रहे हैं और आंदोलन अब धीरे-धीरे सी जे.पी. वालों से आगे निकल रहा है। एक बिना चेहरे की जनता तैयार हो रही है, ऐसा हो सकता है कि कल को कोई घटना हो जाए और जैसे लद्दाख में कुछ नहीं मिला, यहाँ भी न मिले। क्योंकि अगर कोई बड़ी घटना होती है तो 26 दिन की तपस्या मिट्टी मिल जाती है और सरकार को बैठे बिठाए, बहाना जैसे लद्दाख में मिला, तो जो लोग बेवफाई का इल्जाम लगा रहे हैं क्या अगर सोनम अड़े रहते तो सोनम तो खुद शहीद होते, आप मोमबती लगाते और हिंसा होने के बाद कुछ लोग जेल जाते। क्या वो सही था या बिना इस्तीफे के छात्रों पर कोई एफआईआर न हो ताकि किसी छात्र का भविष्य खराब न हो। वो जो पुलिस को पीटे वो भी बचे रह गए। दूसरा जो शहीद पहले हो चुके हैं उनको पैसा मिल गया। तीसरा फास्ट ट्रैक बन गया की अब पेपर लीक का मामला उतना लंबा नहीं जाएगा और चौथा नरेंद्र मोदी सरकार के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ की किसी आंदोलन को इतनी जल्दी खत्म कर दिया गया। सरकार की तरफ से कोशिश की गई। क्योंकि इससे पहले सरकार की टैक्टिक होती थी कि डिले करो, डिले करते जाओ। अब सवाल फिर वही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रात को झुका कर ये सारी मांगे मनवा लेना, समझदारी है या ये सोनम की बेवफाई है?

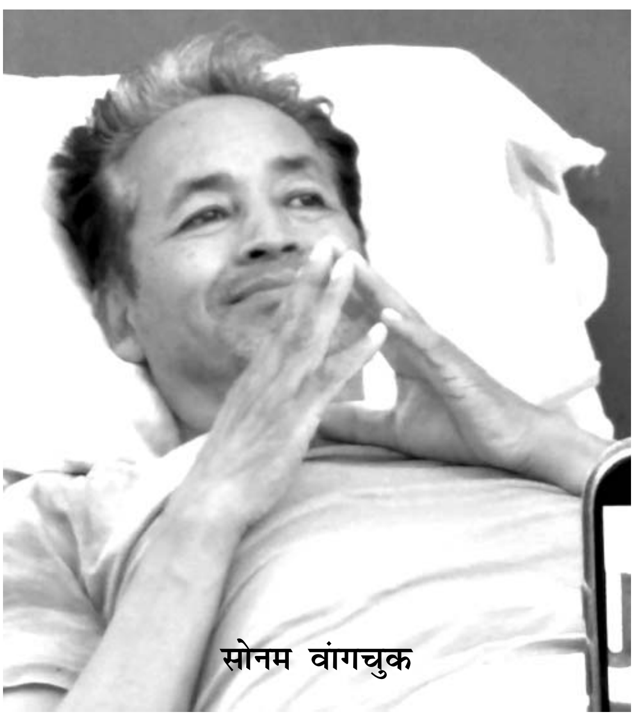
सोनम वांगचुक

बहरहाल, सरकार ने सारी

शर्तें मानते हुए आखिर में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तिफा ले लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिला है। धर्मेंद्र प्रधान के स्थान पर अब प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल ली है। प्रहलाद जोशी अभी अपने पहले से संभाल रहे विभागों के साथ शिक्षा मंत्रालय का काम भी देखेंगे। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें उनके मौजूदा मंत्रालयों के साथ शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपने का आदेश जारी किया है। प्रहलाद जोशी लंबे समय से भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं और पार्टी में कई अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। इससे पहले आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया। ध र्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी। प्रधान ने कहा कि मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। प्रधान ने कहा कि युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा। अब सवाल है कि क्या 12 सालों की नरेंद्र मोदी सरकार में ध र्मेंद्र प्रधान का पहला इस्तीफा हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है? भारत के लोकतंत्र में ऐसी जवाबदेही क्या ये सुखद लग रही है? बात उन बच्चों की करें तो उनके पास क्या था, जो अपने मुद्दों को लेकर लगातार प्रोटेस कर रहे थे। जिनकी पीठ को कितनी बार अलग अलग राज्यों की पुलिस ने पायदान बना लिया था। उनकी लड़ाई शुरू हुई। जंतर मंतर पर उसे मुकाम मिला। लेकिन सोच कर देखिये की उनके पास क्या था। न नेता, न पार्टी, न पैसा, न कोई टी वी एंकर जो सुबह शाम प्राइम टाइम में के लिए चीख चिल्लाए और सवाल उठाए। इनके पास बस एकता थी, वो एकता जो तमाम सेलिब्रिटीज को झुका ले गई। मजबूर कर दिया की उनके मुद्दे पर वो कमेंट करे और उनके सामने दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी वो सरकार जिसके सामने 13 महीनों तक किसान बैठे रहे लेकिन कुर्सी नहीं हिला पाए। जंतर मंतर पर पहलवान बेटियां बैठी रही लेकिन इस्तीफा नहीं ले पाई। लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के बाद भी इस्तीफा नहीं हुआ, मणिपुर महीनों तक चलता रहा लेकिन उसके बाद भी इस्तीफा नहीं हुआ। क्योंकि हर कोई यह मान चुका था कि मोदी सरकार में इस्तीफा नहीं होता है, यही इनकी पॉलिसी है, वो बात न हीं करते। आज देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है और कहना होगा की ये उन बच्चों की बड़ी जीत है। आज सियासत में 12 साल बाद एक शब्द लौटा है जवाबदेही और ये उसकी भी जीत है। इस देश में जवाबदेही के नए दौर की शुरुआत हुई। 12 साल में पहला इस्तीफा, ये किसी चैनल की वजह से नहीं हुआ है, किसी रिपोर्टर की वजह से नहीं हुआ है, यह उन लाखों करोड़ों बच्चों की वजह से हुआ है जो 3 साल से लगातार कोशिश कर रहे थे और जो हफ्तों

धर्मेन्द्र प्रधान

ऐसी सड़कों पर सोए है। हमने भी हमारा काम किया, सवाल पूछा।

गौरतलब है कि धर्मेंद्र प्रधान की चिट्ठी को डिकोड करेंगे क्या उन्होंने कहा है क्या छिपाया है, मोदी सरकार ने क्यों ये इस्तीफा लिया, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और इस सवाल का जवाब पड़ोस के दो देशों से भी जुड़ा हुआ है। वही इस इस्तीफे का क्या फायदा देश की डेमोक्रेसी को होगा? क्या नुकसान बीजेपी को होगा? क्योंकि हर सिक्के का 2 पहलु होता है। अब शुरुआत करेंगे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन को हम डिकोड करें उस चिट्ठी के अन्दर घुसे उससे पहले एक इंटरस्टिंग बात आपको बताते हैं जिस धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी पेपर लीक ने ली है। क्या आप जानते है की इस इंसान की कहानी पॉलिटिक्स आज से 30 साल पहले एक पेपर लीक से शुरू हुई थी। 1997 में ओडिशा में कांग्रेस की सरकार थी और जानकी वल्लभ पटनायक मुख्यमंत्री थे, तब पेपर लीक हुआ था। भुवनेश्वर में सरकारी दफ्तर के सामने 1500 बच्चे आकर बैठ गए और उस भीड़ में ये भी थे एबीवीपी से। लाठियां खूब पड़े थे और वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर हो रही है। लेकिन एक सवाल जो लड़का पेपर लीग के खिलाफ लाठी खाकर मंत्री बना, उसी के रहते उसी उम्र में जिस उम्र में उसे लाठी पड़ी थी, बच्चों को लाठी को मतलब, वो भी वही मांग रहे थे, ये भी वही मांग रहे थे। वो 1997 में बैठे थे या आज बैठे थे। ये थोड़ी कड़वी बात है। लेकिन खैर इस बात को धर्मेंद्र प्रधान को सोचना चाहिए था और सोचा होता तो शायद इस्तीफा न देना पड़ता। लेकिन अब इस्तीफा हुआ है तो इस्तीफा जो हुआ है वो क्या लिख कर हुआ है। वो समझना जरूरी है। अब धर्मेंद्र प्रधान की चिट्ठी पढ़कर पहली बात यह लगती है कि ये कागज गलती से नहीं अपनी तारीफ से शुरू होता है। यानि धर्मेंद्र प्रधान जो प्रोटेस्ट में बच्चे उन्हें गलतियां गिना रहे थे, उन गलतियों को नहीं मानते। वो अपनी तारीफ ऐसी शुरुआत करते हैं। वो अपने 40 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को बताते हैं, वो पेपर लीक की बात करवाई का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि देखिये परीक्षा दोबारा कराई गई, 20 लाख बच्चे बैठे नतीजे आये, गरीब घर के बच्चे पास हुए यानि चिट्ठी शुरू में तो पूरी कामयाबी से। अब यहाँ सोचने वाली बात ये की अगर सब कुछ धर्मेंद्र

प्रधान ने अच्छा किया जैसा चिट्ठी में लिखा है तो फिर इस्तीफा क्यों दिया, क्योंकि दोनों को एक साथ नहीं चल सकते। दूसरी बात ये लगती है कि इस चिट्ठी में जिम्मेदारी नहीं ली गई है, जिम्मेदारी किसी और के सिर डाली गई है। चिट्ठी में इशारा हुआ है की जिम्मेदार कुर्सियों पर बैठे कुछ लोगों ने बच्चों को बहकाया। अब ये इशारा सीजीपी के लोगो पर भी हो सकता है। ये इशारा अरविन्द केजरीवाल, अखिलेश यादव या फिर राहुल गाँधी पर भी हो सकता है तो धर्मेंद्र प्रधान अपनी गलती नहीं मान रहे है, किसी तीसरे पर उँगली उठा रहे है, नाम नहीं लिखा है लेकिन इशारा किया है। इस्तीफा देते वक्त जो सबसे बड़ी बात है, पूरे कागज में कहीं भी उन्होंने एपोलोजी का जिक्र नहीं किया है। माफी कहीं नहीं मांगी है। जिस देश के 22 लाख बच्चों का साल हिल गया और पहली बार नहीं, दूसरी बार था। बीते कई सालो में तो कई पेपर लिक हुए हैं, उन्होंने एक सौरी नहीं कहा। तो चिट्ठी पढ़कर यही लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान ये कहना चाह रहे हैं की मैंने सब कुछ ठीक किया। यह प्रोटेस्ट आया, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है, दूसरे कुछ प्लान कर रहे हैं इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो इसे अगर आप कंक्लूड करे तो ये इस्तीफा नहीं है, ये इस्तीफे की शक्ल में लिखी गई सफाई है और एक बात आपको और याद दिलाते है जो कोई नहीं बताएगा। जब ये मामला शुरू हुआ था तब इन्ही शिक्षा मंत्री ने कैमरे के सामने इस बात को कबूला था की पेपर लीक का कोई सबूत नहीं है। बाद में कहा रक्षक भक्षक बन गए और आज उसी मामले में कुर्सी छोड़ कर जा रहे है।

अब धर्मेन्द्र प्रधान को आत्म मंथन करना चाहिए की कौन सा वाला सच था। अगर कुछ दिन वाला सच था तो आज इस्तीफा किस बात का और अगर आज वाला सच है तो उस दिन देश से क्या कहा गया था। खैर ये धर्मेन्द्र प्रधान की कहानी है। अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से आगे बढ़ कर बात करते हैं। मोदी सरकार का यह पहला इस्तीफा है और इसलिए सवाल उठ रहा है की ये इस्तीफा क्यों हुआ? क्या सरकार डरी? अब इसका जवाब समझना है। तो आपको हिंदुस्तान के पड़ोस के जो देश हैं उनमें बीते कुछ सालो में हुए घटनाओं को देखना पड़ेगा। क्यूंकि साल 2022 में श्रीलंका के नौजवान सड़क पर उतरे थे और राष्ट्रपति को देश छोड़कर जाना पड़ा था। 2024 में बंग्लादेश में जो कुछ हुआ था,

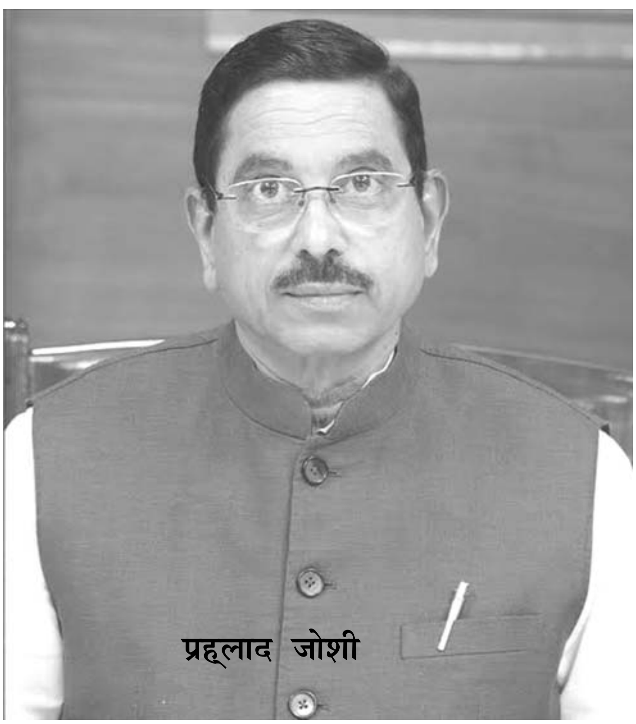

प्रह्लाद जोशी

उसकी शुरुआत भी सरकारी नौकरी के कोटे से हुई थी। यानि वही चीज, जो यहाँ है। परीक्षा और बच्चों के भविष्य और बंग्लादेश में यही चीज आगे बढ़ गयी थी। पंद्रह साल से जमी शेख हसीना को सरकार छोड़नी पड़ी थी। पिछले साल नेपाल में भी जेन जी के प्रदर्शन ने प्रधान मंत्री की कुर्सी ली थी, तो तीन देशों में सेम कहानी जा चुकी थी। वहाँ एक बात और भी कॉमन थी कि वहाँ कोई लीडर नहीं था और यही चीज हर सरकार को डराती है। लीडर हो तो सरकार के पास तीन रास्ते होते है- या तो उसे खरीद लो या लीडर कोई फंसा दो या बदनाम कर लो। लेकिन अगर लीडर नहीं होता है तो फिर तीनों बंद हो जाते हैं। आप किसे खरीदोगे, किसे अन्दर करोगे, किस पर विदेशी पैसे का ठप्पा लगाओगे। जंतर मंतर पर सरकार को यही दिक्कत है, जंतर मंतर पर अभिषेक दहिया या एक्स वाई जो भी थे। यह ना भी रहे तो भी प्रोटेस चलता और आपने देखा सोनम वांगचुक के जाने के बाद भी प्रोटेस रुका नहीं। अब ये तो पड़ोस की बात थी, घर के अन्दर की बात करते है। असली वजह केवल विदेश में नहीं थी, दिल्ली में भी बैठी थी। पहली वजह ये कि इस बार ठप्पा लगाने के लिए कोई गिरबान नहीं मिला। किसान को कह सकते थे की एक राज्य के हैं, वहाँ पर खालिस्तान वाला एंगल मिल गया था, पहलवान वे कह सकते हैं, गिनती के हैं। बच्चों को आप क्या कहेंगे। ये हर राज्य में है, हर जाति में है, हर पार्टी के वोटर में है। आई टी सेल चलाने वालों के घर में भी बच्चा तैयारी कर रहा है। सबसे बड़ी बात ये थी कि ये बीजेपी के लिए भी आने वाले समय का वोटर था। जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, या तो उसने 12 बार वोट दिया है, 2 बार, 1 बार वोट दिया होगा या अगली बार, ऐसी पहली बार वोट देगा और पॉलिटिक्स में परसेप्शन बहुत बड़ी चीज होती है। इस बार यह परसेप्शन बन गया था की मोदी साहब सुनते नहीं है, मोदी साहब इस्तीफा नहीं लेते है। उनको लेकर बार बार बताया जा रहा था की डेमोक्रेसी में वो तानाशाह है, तानाशाही करते है, जिसको मन करता है, दबा देते है, लाठी चला देते हैं, संवाद नहीं करते हैं और अगर नोटिस किया हो तो मोदी जी ने ये सारे परसेप्शन तोड़ने की कोशिश की है, संवाद भी किया, सारी बात भी मानी और इस्तीफा भी दिलवाया। भारत पूरी तरह से हमारे पड़ोस के देशों की तरह नहीं रहा है। जैसे बंग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, उन तीनों के जो हेड ऑफ स्टेट थे, उनसे मोदी जी थोड़े ज्यादा स्मार्ट है, उन्हें झुकना कब है, कब संभलना है, कब करना है। ये शायद बेहतर समझ में और इंस्टाग्राम वाला मूव ऐक्चवली बहुत शानदार था। जिस इंस्टाग्राम पर लोग पानी पी पी कर गाली दे रहे थे, वही पर उनको लेकर फनी फनी मीम्स बनाए जा रहे है।

अब सवाल है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो इसका फायदा किसे होगा? तो बता दें कि सबसे बड़ा फायदा हिन्दुस्तान के लोकतंत्र को हुआ है और यह मैं इसलिए कहा जा रहा क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से 12 साल बाद हिन्दुस्तान में एक शब्द की वापसी हुई है, जिसका नाम है जवाबदेही। भारत की डेमोक्रेसी में 12 सालो में

दतिया में कांग्रेस की जीत

बांकीपुर में जनसुराज की जीत

हम ये मान चुके थे कि कुर्सी अलग चीज है, जिम्मेदारी अलग चीज है। आप याद कीजिये हिंदुस्तान में ट्रेन पलटी, पेपर लिक हुआ, पुल गिरा, जवाब हमेशा किसी अफसर पर, किसी एजेंसी पर। मणिपुर जलने से लेकर लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी चढ़ने तक, बड़ी बड़ी घटनाओं में भी मंत्रियों से इस्तीफे नहीं लिए गए। आज पहली बार जवाब उस आदमी तक पहुँचा जो फैसला लेने वाली कुर्सी पर बैठा था और इसलिए हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा दिन है। कुर्सी वाले को भी यह याद रहे की उसका मकान नहीं है, किरायदार हैं। जब तक तरीके से काम होगा तब तक कुर्सी है। दूसरा फायदा यह हुआ कि समाज को भी पता चल गया की हर बार नेता के सहारे जंग नहीं जीती जाती। अगर आपके पास मुद्दा है, आप संगठित है तो बिना पार्टी, बिना झंडा, बिना चन्दा, बिना स्टेज भी आप मजबूत से मजबूत सरकार को झुका सकते हैं और इस बार क्योंकि सड़क पर बच्चा बैठा था तो बच्चे ने जिद करके ये काम करवा लिया। ये बहुत बड़ी चीज है। ये अलग-अलग संगठनों को जिनके साथ नाइंसाफी होती है, भविष्य में उन्हें बहुत ताकत देगा। अब वो बात जो शायद कोई नहीं बोलेगा। अब इस इस्तीफे का फायदा सरकार को भी हुआ है। लेकिन सरकार के फायदे पर जाए उससे पहले समझते हैं। सरकार ने क्या किया, तो बता दें पेपर लिक पर सख्त कानून का मसौदा नई कैबिनेट से पास हुआ, जिसमें 10 साल की सजा, 10 करोड़ तक के जुर्माने की बात कही गयी, फास्ट्रेक कोर्ट का एलान किया गया, वांगचुक को भरोसा दिया गया।

अब सरकार को इससे क्या फायदा होगा? तो बता दें कि आंदोलन का एक बड़ा सिरा आज से सरकार के हाथ में चला गया। क्योंकि आंदोलन की एक बड़ी खतरनाक बात होती है की जब एक बार वो वायरल हो जाता है तो फिर वो हर दिन एक नए शहर, एक नए गाँव और लाखों नए लोगों को जोड़ता है और यह हो रहा था। बीजेपी के पैरों तले जमीन खिसक रही थी। वो सीजेपी जिसको मजाक में शुरुआत में लिया गया था, वो अगर कल को प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा मांगने लगती तो! ज्ञात हो कि कई प्रोटेस्ट में लोग खुद को आग लगा लेते हैं। कई बार ऐसा होता है। जिस इंटेंसिटी के साथ पूरा देश इस प्रोटेस्ट में जुड़ा था, मोदी सरकार की हवा टाइट हो जाती है। वहाँ तक बात पहुँचे, उससे पहले सरकार ने रोक लिया और ये सरकार के लिए एडवांटेज हो गया। यह फायदा हुआ है। अब इसकी कीमत क्या सरकार ने दी? एक ऐसा मंत्री जो शायद इस वक्त सरकार की कमजोर कड़ी था। तो सरकार ने एक आदमी खोया, लेकिन एक बड़ा मुद्दा जो सरकार के

खिलाफ जा रहा था, उसे फिलहाल काफी हद तक कंट्रोल कर लिया। आगे क्या परसेप्शन बनता है, वो देखने वाली बात हो गया। दूसरा फाइनल सरकार का ये है की सरकार के पास आज से एक नई लाइन आ गई है। सरकार आज से कह सकती है कि हम जनता की सुनते हैं। आगे आने वाले चुनावों में बार-बार लाइन रिपीट की जाएगी। मोदी जी कहेंगे कि देखिये जनता कुछ कहें तो हम मान लेते हैं, आपके लिए करते हैं। मतलब ये वाला परसेप्शन जो है की वो तानाशाह है, उसको बीजेपी तोड़ने की कोशिश करेगी। नौजवान वोटरों के सामने ये लाइन मजबूत हो सकती है, क्योंकि उन्हीं से संवाद है। अगली बार के वोटर वही है।

बहरहाल, देश में जो अस्थिरता जो छात्रों के आंदोलन से आयी उसमें जितने छात्र गलत हैं तो उतने ही सरकार द्वारा देर से लिया गया फैसला। प्रधानमंत्री में विकसित भारत की बात करते हैं जिसके लिए पढ़े-लिखे लोगों का होना जरूरी है। जो छात्र देश के भविष्य निर्माता हैं, उन्हें शिक्षा में भ्रष्टाचार दिखाकर बाधित नहीं किया जा सकता। आज के ये जेन जी ने छात्रों की ताकत क्या होती है, सरकार को दिखाया। लाठियां खाई, हिंसक भी हुए और हिंसा में बेकसूर पुलिस वालों को भी गंभीर चोटे आयी किन्तु यह आन्दोलन सरकार की आंखों से पहले काले चश्मे को उतारना भी उतना ही जरूरी था। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तिफे के बाद प्रह्लाद जोशी नये शिक्षा मंत्री बनाये गये हैं किन्तु उनके पर शिक्षा नीती में सुधार और शिक्षा प्रणाली में भ्रष्टाचार को खत्म करना एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। इसके साथ ही एक आंदोलन शिक्षा से ही जुड़ा यूजीसी का है, जो जारी है। उसे तत्काल खत्म करना होगा, वरना जो हालात अभी राजधानी दिल्ली समेत बिहार और अन्य प्रदेशों में देखने को मिला, पुनः दोहरा सकता है। फैसला सरकार के हांथों में है कि उन्हें क्या करना है। 12 साल की मोदी सरकार 15 साल तो पूरी कर लेगी पर क्या उसके बाद भाजपा का विरोध जिस प्रकार देश की जनता कर रही है, सत्ता में फिर से आने देगी! उदाहरण के लिए बांकीपुर और दतिया विधानसभा पर हुए उपचुनाव के परिणाम सामने हैं और यह भाजपा के लिए मंथन का विषय है।●

Rahul Gandhi's protest forces police to lodge complaint of pellet injury

Congress party leader Rahul Gandhi on Friday staged a sit-in outside a police station in New Delhi on Friday after authorities allegedly refused to register the complaint of a student protester's pellet injuries suffered during last month's Cockroach protest. Gandhi had accompanied Sahil Lochab to the Parliament Street police station in New Delhi to register a report of his complaint. His sister and Congress leader Priyanka Gandhi Vadra later joined him in the sit-in protest.

According to the Congress party, Lochab had previously approached police on August 14 and August 17 but did not receive an acknowledgement or details of the investigating officer. Gandhi, while talking to media, said medical reports showed that more than 200 pellets were lodged in Lochab's body, including three in his eye, resulting in loss of vision. He also said some pellets were lodged near Lochab's heart and could not be removed. Lochab's lawyer said police had only stamped and acknowledged the complaint after Gandhi's intervention, and claimed medical reports confirmed that pellet guns had been used.

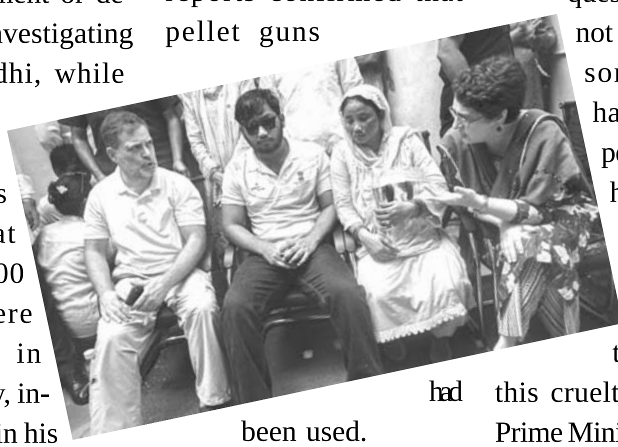

Gandhi alleged that Delhi Police had denied firing pellet guns during the protest and demanded an investigation into how Lochab sustained the injuries. "Delhi Police has said that they did not fire the pellets," Gandhi said. "So, there is only one question: If you did not fire them, then someone must have fired these pellets." "Neither has Home Minister Amit Shah offered any explanation to the students for this cruelty, nor has the Prime Minister apologized to them. Now, when Sahil wants to file an FIR for justice, even that is not being allowed," Gandhi posted on X.

After CJP, 'Dimagi Naxal Janta Party' Emerges on Social Media, Gets 1.8 Lakh Instagram Followers in 24 Hrs

Amid the political controversy over Prime Minister Narendra Modi's reference to “dimagi naxals” in his 80th Independence Day address, a new campaign has emerged on social media under the name “Dimagi Naxal Janta Party” (DNJP).

The development comes days after the emergence of the satirical “Cockroach Janta Party” (CJP). A social media account using the name “Dimagi Naxal Janta Party” recently gained significant attention, particularly on Instagram. The Instagram page crossed 1.8 lakh followers in a single day. Its slogan was “Think | Research | Resist.” The account had around 68 posts and followed 35 accounts. The Instagram account was suspended for some time in the morning but now has been restored.

Meanwhile, a new account on X using the name “Dimagi Naxal Janta Party” (DNJP) has also surfaced. The account, @DNJP_India, currently follows 17 accounts, including Congress leader Rahul Gandhi, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav, AAP leader Arvind Kejriwal, TMC leader Mahua Moitra, musician Vishal Dadlani, YouTuber Dhruv Rathee, comedian Kunal Kamra, actor Prakash Raj and fact-checker Mohammed Zubair.

A website using the name “Dimagi Naxal Janta Party” has also appeared online. According to the website, the initiative was established on August 16, 2026, and describes itself as a movement rather than a political party of office. Its message includes the line: “Dimagi Bano, Bewakoof Nahi (Be intelligent, not foolish.)”

What did PM Modi say about 'Dimagi Naxals'?

Prime Minister Narendra Modi used the term “dimagi naxals” during his Independence Day speech while highlighting the government's achievements in combating Maoist insurgency and warning about what he described as threats that continue to exist beyond armed Naxalism. “We have succeeded in eliminating armed Naxals from the forests and liberating the nation from that crisis. However, while armed Naxals are gone, dimagi (intellectual) Naxals are lurking around,” he said.

The remark sparked a political reaction, with senior Congress leader P Chidambaram saying that he was proud to be a “dimagi naxal”. Union Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju, however, said the Prime Minister had not specifically used the term to refer to opposition leaders.

Rijiju said the phrase was intended for people who support Maoists, reject the Constitution, back separatism, support Article 370 or advocate severing the “chicken neck” corridor connecting the northeastern states with the rest of India.

DNJP follows the satirical trend

The emergence of DNJP follows the launch of the Cockroach Janta Party (CJP), a satirical platform launched by Abhijeet Dipke. The CJP was reportedly created after Chief Justice of India Surya Kant was said to have compared unemployed young people to “cockroaches”. During a court hearing on May 15, the CJI reportedly said that some unemployed youngsters become journalists, RTI activists or social media users and “start attacking everyone”.

The Chief Justice later clarified that his remarks had been misquoted and taken out of context. The emergence of the “Dimagi Naxal Janta Party” appears to continue the trend of using political satire and social media campaigns to respond to controversial public remarks. The initiative's future and whether it develops into a larger online movement remain to be seen.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रयागराज में दर्द, डेटा और दौलत की बात की। उन्होंने कहा कि आज देश का युवा नौकरी के लिए तरस रहा है। न मैन्यूफैक्चरिंग में, न स्टार्टअप्स में और न ही सरकारी नौकरी है। जबकि 40 करोड युवा देश की असली ताकत है। हालांकि उन्होंने कहा कि आज नौजवानों ने जो ताकत दिखाई, वो काबिल ए तारीफ है। राहुल गांधी ने कहा कि आज शाम मैं आपसे दर्द, डेटा और दौलत की बात करना चाहता हूं। आपका दर्द, आपका डेटा, मगर आपका धन नहीं, जो आपका होना चाहिए। राहुल ने इस दौरान मंच पर 7 से ज्यादा छात्र-छात्राओं से बात की। उनसे शिक्षा, रोजगार से जुड़े सवाल किए। उनके साथ प्रियंका गांधी की बेटी मिराया भी मौजूद थीं। इस कार्यक्रम में यूपी के 23 जिलों से छात्रों को बुलाया गया था। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचे थे। वहां उन्होंने 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार को घेरा और युवा शक्ति का जिक्र किया। उन्होंने जोर देकर बोला कि आज के नौजवान ने जो हिम्मत दिखाई है, वो काबिले तारीफ है।

राहुल गांधी ने कहा कि आज शाम मैं आपसे दर्द, डेटा और दौलत की बात करना चाहता हूं। आपका दर्द, आपका डेटा, मगर आपका धन नहीं, जो आपका होना चाहिए। आप भारत की शक्ति हो, भारत की शान हो, भारत की स्ट्रेंथ हो और जब मैं कहता हूं आप भारत की शक्ति हो, भारत की स्ट्रेंथ हो। मैं हर हिंदुस्तान के नागरिक, हर यूथ की बात कर रहा हूं। इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूं। आप सब में इंटेलिजेंस है, इमेजिनेशन है, कैपेसिटी है और अगर ये देश आगे बढ़ेगा, तो आपके बल पर, आपकी स्ट्रेंथ पर इस देश का फ्यूचर बनेगा। इस युवा ने जो कहा है, वो हिंदुस्तान के युवाओं के दिल की बात है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि आप जैसे एनर्जेटिक युवा इस देश में रहते हैं, ये इस देश की स्ट्रेंथ है। चाइना की बात होती है, अमेरिका की बात होती है, रशिया की बात होती है, इंडिया के यूथ के सामने, इंडिया के यूथ पोटेंशियल के सामने ये सब लोग कुछ नहीं है। एक और चीज हुई है। 21वीं सदी में अगर देश प्रगति करता है तो दो चीजों के बल पर करता है। यूथ पोटेंशियल जो आप में है और डेटा जो आप क्रिएट करते हो। कांग्रेस नेता बोलते हैं कि डेटा से आप एआई बना सकते हो। मगर एआई से आप डेटा पैदा नहीं करते हो, कर सकते हो। और ये डेटा हिंदुस्तान का है और आपका है। आप इसको क्रिएट करते हो। ये आप बनाते हो, ये आपका इमेजिनेशन है। ये हिंदुस्तान की पूंजी है, स्ट्रेंथ है, एसेट है।

❖ राहुल ने कहा कि युवाओं के लिए पांच दरवाजे थे, वो सारे बंद कर दिए गए हैं :-

☞ दुनिया में आज मेड इन चाइना, मेड इन वियतनाम, मेड इन बांग्लादेश मिलेगा, लेकिन मेड इन इंडिया नहीं मिलेगा। क्योंकि नोटबंदी और गलत GST ने मैन्यूफैक्चरिंग सिस्टम को खत्म कर दिया है।

☞ स्टार्टअप इंडिया कहां चला गया। हिंदुस्तान के बैंक आपको एक रुपया नही देंगे, अंबानी-अडाणी को लाखों करोड रुपए देंगे। छोटे व्यापारियों को बैंक लोन नहीं मिलता।

☞ सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले 150 कैंडिडेंट्स में से सिर्फ 1 युवा को सरकारी नौकरी मिलती है।

☞ पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट करने से नौकरी खत्म हो गई। 2014 से पहले जिन पब्लिक सेक्टर में 14 लाख जॉब थी, 2026 में सिर्फ 7 लाख बचीं।

☞ कॉर्पोरेट जॉब में AI की वजह से नौकरी खत्म हो गई हैं।

❖ प्रयागराज प्रोटेस्ट में राहुल की खास बातें :-

☞ भारत के करीब 40 करोड युवा देश की असली ताकत।

☞ सर्टिफिकेट रोजगार की गारंटी नहीं देता।

☞ 1 हजार युवाओं में से सिर्फ 12 को स्थाई नौकरी मिलती है।

☞ युवाओं का डेटा बडी कंपनियों को दिया जाता है।

☞ रील बनाना 21वीं सदी का नशा है।

☞ स्टूडेंट पढाई में पैसा खर्च करता है, लेकिन नौकरी के दरवाजें बंद हैं।

☞ न मैन्यूफैक्चरिंग है, न स्टार्टअप्स, न सरकारी नौकरी।

❖ स्टूडेंट के दिल में मोहब्बत होनी चाहिए :- आपने अंधेरे में टार्च जला दी। आप सब बात समझ गए। स्टूडेंट के दिल में नफरत नहीं मोहब्बत होनी चाहिए। मैंने पिछली स्लाइड में मोदी, भागवत, अडाणी की फोटो दिखाई, लेकिन आपको सिस्टम को खत्म टाटा बॉय बॉय करना है। ये सब आपको प्यार के साथ करना है। मैं आपके साथ खड़ा हूं और आगे भी रहूंगा।

❖ राहुल से छात्रा ने कहा- पुलिस ने एके-47 चलाई :- राहुल ने बिहार की छात्रा से बात की। उसने बताया- बिहार पुलिस ने पटना में प्रदर्शनकारियों को पीटा। 23 जुलाई को हमने एक और प्रोटेस्ट रखा। लेकिन उससे पहले पुलिस और RAF मौजूद था, फिर अगले दिन सिवान में पुलिस ने एके-47 चलाई। एक छात्र की मौत हो गई। 25 जुलाई को आप जब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जश्न मना रहे थे। तब हम बिहार में डरे बैठे थे, कब कहां से पुलिस हमें उठा ले जाए। लाइब्रेरी से छात्रों को ले गई।

❖ राहुल ने पटना के छात्र से सुनी प्रदर्शन की कहानी :- एक छात्र ने स्टेज पर आकर बताया कि 22 जुलाई को पटना में प्रदर्शन के दौरान हमारे ऊपर पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया। उनका टारगेट था सिर पर मारो या पैर में। आंसू गैस के गोले छोड़े। इनकी वर्दी में बैच भी नहीं थे। ये एंबुलेंस नहीं आने दे रहे थे। थ्री इडियट मूवी की तरह स्कूटी में अस्पताल ले गया। बाद में मुझे 15 घंटे थाने में बिठाया गया। हम पहले नौकरी के लिए आंदोलन करें, फिर पेपर के लिए करें, फिर रिजल्ट के लिए करें। अरे हम छात्र हैं या आंदोलनजीवी हैं। हम बिहारी हैं सत्ता पलट भी सकते हैं। राहुल बोले, मैं भी जब पहली बार बोला था, नर्वस था। आप यहां खुलकर बोले, घर की तरह।

उद्घाटन के 22 दिन बाद धंसा लखनऊ- कानपुर एक्सप्रेसवे

उद्घाटन के महज 22 दिन बाद ही लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का 'दम' उखड़ने लगा है। कुल 8 जगहों पर धंस चुकी इस सड़क की मरम्मत के लिए इंजीनियरों ने अब 'हास्यास्पद थेरेपी' शुरू की है। सड़क को सुखाने के लिए बड़े-बड़े पंखे लगा दिए गए हैं। इस अनूठे 'तकनीकी चमत्कार' को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तीखा तंज कसा है, वहीं चौतरफा फजीहत के बाद एनएचएआई (NHAI) ने टोल वसूली रोक दी है।

❖ **22 दिन में खुली 'विकास' की कलई** :- उत्तर प्रदेश के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर इन दिनों सड़कों को पंखे और ब्लोअर से हवा दी जा रही है। वजह बेहद साधारण है। 14 जुलाई को चालू हुआ यह एक्सप्रेसवे जगह-जगह से धंस गया है और बारिश के मौसम में तेजी से मरम्मत निपटाने के लिए ठेकेदार पंखों का सहारा ले रहे हैं। वायरल वीडियो के मुताबिक 60 मीटर के दायरे में 10 पंखे लगाए गए हैं।

❖ **26 जुलाई को पहली दरार** :- 14 जुलाई को बड़े गाजे-बाजे के साथ चालू हुए इस एक्सप्रेसवे की उम्र एक महीना भी पूरा नहीं कर सकी। 26 जुलाई को उन्नाव जिले के कुरारी गांव के पास (किलोमीटर 64 पर) सड़क का डामर अचानक उखड़ गया और अगल-बगल की जमीन धंस गई। देखते ही देखते 22 दिनों के भीतर एक्सप्रेसवे एक या दो नहीं, बल्कि 8 अलग-अलग स्थानों से धंस गया और कई जगहों पर जानलेवा गड्ढे बन गए। जिस सड़क पर गाड़ियों को 100 किमी/घंटे की रफ्तार से दौड़ना था, वहां अब गाड़ियां गड्ढे बचाती नजर आ रही हैं।

❖ **क्या कहा सपा नेता अखिलेश यादव ने?** :- सड़क सुखाने के लिए पंखे लगाने का वीडियो और तस्वीरें सामने आते ही विपक्षी दलों ने सरकार को आड़े हाथों लिया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर इस अनोखी मरम्मत का जमकर मजाक उड़ाया है। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा- ये है भाजपाई तरक्की की नई हवा। कुछ दिनों पहले ही जिसका उद्घाटन हुआ हो, उस सड़क को मरम्मत की जरूरत पड़ गई और एक्सप्रेस स्पीड से मरम्मत को सुखाने के लिए पंखे का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये हास्यास्पद है। 2-3 हफ्ते में ही जिस एक्सप्रेसवे का दम उखड़ने लगा है, उस पर चलने का जोखिम कौन उठाएगा? उन्होंने 'अटल प्रोग्रेस वे' का जिक्र करते हुए आगे कहा कि सवाल यह भी है कि योजनाएं सिर्फ कागजों में बनकर 'हिस्सा-बांट' का जरिया बन रही हैं या सच में बनेंगी। भाजपा राज में बना हर निर्माण चलता कम है... धंसता, ढहता और गिरता ज्यादा है।

❖ **NHAI एक्शन में, टोल वसूली रोकी** :- इस मामले में किरकिरी होने के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) की नींद खुली है। NHAI के मुख्य महाप्रबंधक (उत्तर प्रदेश) गौतम विशाल ने बताया कि जब तक क्षतिग्रस्त हिस्से की पूरी तरह गुणवत्तापूर्ण मरम्मत नहीं हो जाती, तब तक लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली पूरी तरह से रोक दी गई है। निर्माण कार्य करने वाली कंपनी के साथ-साथ प्रोजेक्ट की निगरानी कर रहे स्वतंत्र इंजीनियरिंग सलाहकारों और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। टोल न वसूलने से होने वाले पूरे वित्तीय नुकसान की भरपाई निर्माण एजेंसी (PNC) से ही की जाएगी।

रा उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन के भीतर घटे घटनाक्रम ने राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया है। अमूमन शांत और सख्त अनुशासन के लिए जाने जाने वाले विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना विपक्ष के आचरण और सदन में हुई नारेबाजी से खासे आहत नजर आ रहे हैं। विधानसभा में सदस्यों के रवैये से दुखी होकर स्पीकर ने यहां तक कह दिया कि वे इस बात का आकलन कर रहे हैं कि वे इस गरिमामयी पद के लायक हैं भी या नहीं।

❖ **सदन में ऐसा क्या हुआ जिससे दुखी हुए सतीश महाना? :-** उत्तर प्रदेश विधानमंडल के सत्र के दौरान मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायकों ने लगातार नारेबाजी और हंगामा किया :-

☞ **चंदा चोर के नारों पर तीखी बहस :-** विपक्ष द्वारा 'चंदा चोर, गद्दी छोड़' के नारे लगाए जाने पर अध्यक्ष पीठ का धैर्य जवाब दे गया। सतीश महाना ने कड़ा पलटवार करते हुए कहा, 'अगर आप में से किसी ने चंदा दिया हो, तो रसीद दिखाओ।'

☞ **मुख्यमंत्री के पोस्टर लहराना :-** बहस के दौरान सपा विधायक सचिन यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर वाले पोस्टर लहराए और आसन के सामने आकर नारेबाजी की।

☞ **सख्त कार्रवाई :-** आसन की अवमानना और मर्यादित आचरण न करने के कारण अध्यक्ष ने विधायक सचिन यादव को पूरे सत्र के लिए सदन से निष्कासित कर दिया।

☞ **आसन की पीड़ा :-** सदन लोकतंत्र का मंदिर है। जब जनप्रतिनिधि नियमों और परंपराओं को ताख पर रखकर वेल में आकर हंगामा करते हैं और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे संसदीय मर्यादा तार-तार होती है।

❖ **जल्द बताऊंगा कि पद के लायक हूं या नहीं :-** सदन के भीतर और बाहर जिस तरह का माहौल बना, उससे क्षुब्ध होकर स्पीकर सतीश महाना ने कहा कि वे निष्पक्ष रहकर सदन चलाने का हरसंभव प्रयास करते हैं। इसके बावजूद जब दोनों पक्षों (विशेषकर विपक्ष) से सहयोग नहीं मिलता और आसन पर लांछन लगाए जाते हैं, तो यह बात मानसिक रूप से आहत करती है। उन्होंने भावुक लहजे में संकेत दिया कि वे जल्द ही इस बात का सार्वजनिक रूप से जवाब देंगे कि क्या वे इस गरिमामय पद के योग्य हैं या नहीं।

❖ **यूपी की राजनीति पर क्या होगा असर? :-** सतीश महाना का यह बयान केवल एक भावुक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की संसदीय राजनीति के लिए बड़ा संदेश है। जब से सतीश महाना ने विधानसभा अध्यक्ष का पद संभाला है, उन्होंने कई नई पहल की हैं-जैसे डिजिटल विधानसभा (e-Vidhan) और सदस्यों को बोलने का समान मौका देना। ऐसे में उनका यह क्षोभ सदन के संचालन और भावी सत्रों के नियमों को और अधिक कड़ा बनाने की ओर इशारा करता है।

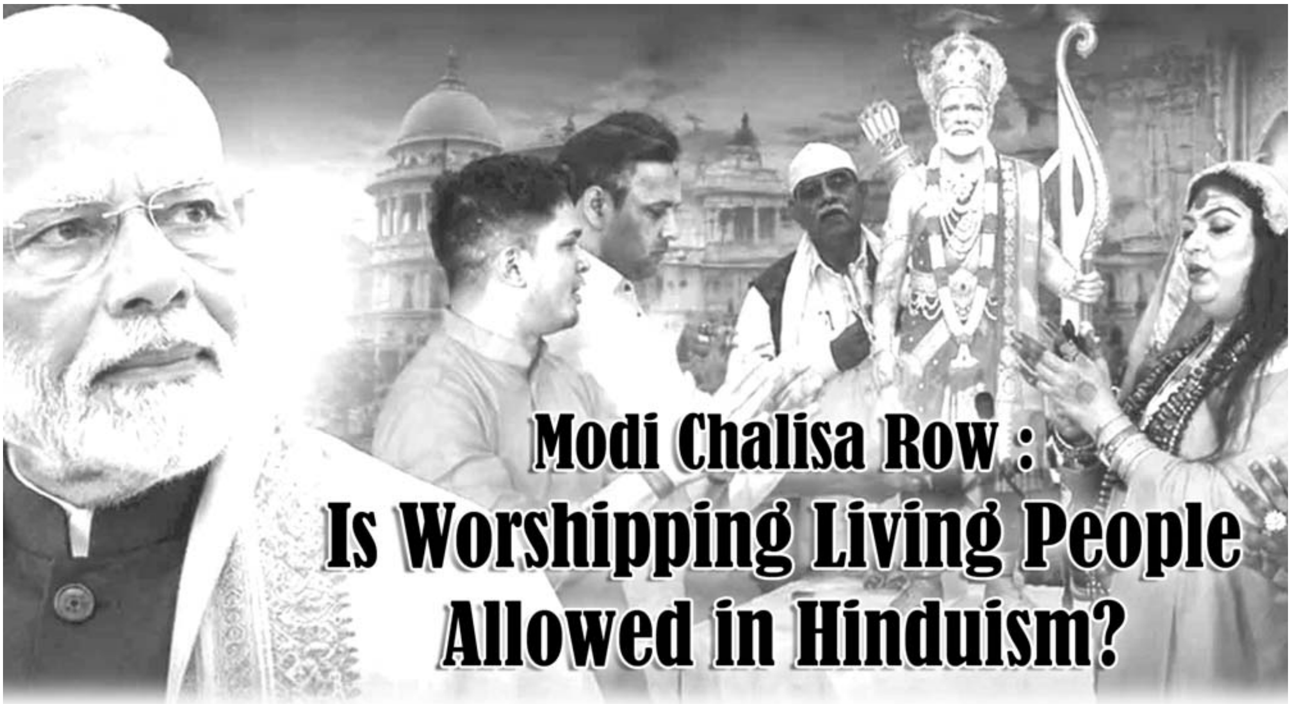

Modi Chalisa Row : Is Worshipping Living People Allowed in Hinduism?

I Across India, there have been instances where politicians, actors and other public figures have been elevated to the status of gods, with temples built in their names and rituals such as aarti and worship performed in their honour. Reports of temples dedicated to personalities such as Sachin Tendulkar, Rajinikanth, Amitabh Bachchan, Narendra Modi and Sonia Gandhi have surfaced from time to time.

The issue has once again come into focus amid discussions surrounding a so-called "Narendra Modi Chalisa." This has raised a broader question: according to Hindu religious traditions and scriptures, what is the difference between respecting an influential person and worshipping them as a divine being? Many traditional interpretations of Hindu scriptures hold that worship is directed towards the divine, while reverence and respect may be offered to teachers, saints, ancestors and great personalities. However, interpretations and practices vary across Hindu traditions and communities.

Worship and Person Worship in Hindu Traditions

According to one traditional interpretation, Hindu scriptures prescribe the worship and devotion of God, goddesses and divine forms, while treating the worship of ordinary human beings as distinct from divine worship.

The Bhagavad Gita discusses different forms of worship based on the nature of an individual's faith. One verse often cited in such discussions is from Chapter 17, Verse 4 :

"Yajante sattvika devan
yaksha-rakshamsi rajasah,
pretan bhuta-ganams
chaanye yajante tamasa janah."

Meaning : Those of a sattvic nature worship the gods; those of a rajasic nature worship yakshas and rakshasas; while those of a tamasic nature worship spirits and other such beings.

Another verse from Chapter 9, Verse 25 states :

"Yanti deva-vrata devan
pitrun yanti pitru-vratah,
bhutani yanti bhutejya
yanti mad-yajino 'pi mam."

Meaning : Worshippers of the gods attain the gods, worshippers of the ancestors attain the ancestors, those who worship spirits attain such beings, while those devoted to the Supreme attain Him.

These verses are often interpreted to distinguish between devotion directed towards the Supreme and other forms of worship.

Devotion to the Supreme

The Bhagavad Gita repeatedly emphasises surrender and devotion to the Supreme Being. Chapter 18, Verse 62 says :

"Tam eva sharanam
gaccha sarva-bhavena Bharata,
tat-prasadat param
shantim sthanam
prapsyasi shashvatam."

Meaning : O Arjuna, take refuge in Him alone with your whole being. By

His grace, you will attain supreme peace and the eternal abode.

Similarly, Chapter 8, Verse 8 states :

"Abhyasa-yoga-yuktena
chetasa nanya-gamina,
paramam purusham
divyam yati
Parthanuchintayan."

Meaning : One who constantly meditates upon the Supreme Divine Being with a mind disciplined through the practice of yoga ultimately attains Him.

Chapter 8, Verse 16 further says :

"A-brahma-bhuvanal
lokah punar-avartino
'rjuna,
mam upetya tu Kaunteya
punar janma na vidyate."

Meaning : All worlds, up to Brahmaloka, are subject to return and rebirth, but one who attains the Supreme does not take birth again.

The Debate Over Worshipping Saints, Ancestors and Historical Figures

The article's central argument is based on a particular scriptural interpretation that distinguishes respect and remembrance from formal worship. Under this view, saints, teachers, ancestors, rulers and other respected individuals may be honoured for their contributions, but should not necessarily be equated with God.

Practices such as visiting samadhis, dargahs or memorials are also viewed differently across religious and cultural traditions. For many people, these places represent faith and devotion, while others regard them primarily as sites of remembrance, history or respect rather than divine worship.

Similarly, temples and memorials dedicated to historical figures or acts of sacrifice may hold deep cultural and emotional significance, even as debates continue over whether such personalities should be treated as divine beings.

What Does the Concept of the 16 Kalas Mean?

Traditional Hindu philosophy also contains the concept of "kalas" or degrees of divine manifestation, although interpretations differ across texts and traditions.

According to one traditional explanation, an ordinary human being is associated with a limited manifestation of these qualities, while rishis, saints and great spiritual personalities are believed to possess a higher degree of spiritual consciousness. Divine beings are described as possessing greater manifestations of these qualities.

Lord Rama is traditionally described as possessing 12 kalas, while Lord Krishna is associated with 16 kalas, representing a complete manifestation in certain Hindu philosophical traditions. Based on this interpretation, the article argues that the worship of a mortal human being should not be equated with the worship of a divine form.

Sattvic, Rajasic and

Tamasic Forms of Worship

Hindu philosophy broadly classifies human tendencies and forms of worship into three categories :

Sattvic : Worship associated with purity, selflessness and devotion to the divine.

Rajasic : Worship motivated by worldly desires, rewards or personal gains.

Tamasic : Worship associated with ignorance, fear or blind attachment.

The classification of a particular practice, however, can vary depending on the scriptural tradition and interpretation being followed.

Chalisa and Stuti : Their Traditional Context

Texts such as the Hanuman Chalisa and Durga Chalisa are devotional compositions associated with revered divine figures and forms of worship. The growing discussion over compositions dedicated to living political leaders or public personalities has therefore sparked a debate over the boundaries between devotion, admiration and personality cults.

Critics of person worship argue that writing a chalisa in the name of a living political or public figure may blur the distinction between respect for an individual and religious devotion.

Respect Is Not the Same as Worship

A central point in this debate is the difference between respect and worship. Hindu traditions have long emphasised respect for teachers, saints, national figures, rulers and individuals who have made important contributions to society.

However, critics of personality cults argue that admiration should not automatically lead to religious rituals or the declaration of a living person as a god.

The Debate Over Temples and Rituals in Name of Narendra Modi

The discussion surrounding the alleged "Narendra Modi Chalisa" has brought this issue back into the spotlight. Critics argue that when temples are built or devotional rituals are performed in the name of living political leaders, it can encourage a culture of excessive personality worship.

The original argument further states that individuals whose names are used for such practices have a moral responsibility to clarify their position if they believe such rituals are inappropriate. Supporters, however, may view such expressions as acts of admiration rather than formal religious worship.

राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और धांधली के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो ने अपना अनशन समाप्त कर दिया। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से वीडियो कॉल पर हुई बातचीत और उनकी अपील के बाद देवेंद्र ने अन्न-जल ग्रहण किया। हालांकि, अनशन समाप्त होने के बावजूद छात्रों का आंदोलन जारी है। इस बीच, खबर है कि सीजेपी नेता अभिजीत दीपके भी रांची पहुंचने वाले हैं। झारखंड की राजधानी रांची में राज्य लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा प्रणालियों में धांधली और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर छात्रों का प्रदर्शन उग्र रूप ले चुका है। लद्दाख के प्रसिद्ध पर्यावरण व सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने वीडियो कॉल के माध्यम से देवेंद्र महतो से बात की। वार्ता के दौरान वांगचुक ने आंदोलन के मुद्दों पर चर्चा की और देवेंद्र की लगातार गिरती सेहत पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए उनसे अनशन वापस लेने का आग्रह किया। सोनम वांगचुक की अपील और छात्रों के भारी दबाव के बाद देवेंद्र महतो ने अपना अनशन समाप्त करने का निर्णय लिया। लगातार चार दिनों के उपवास के कारण उनकी स्थिति बिगड़ रही थी। रांची सदर अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार उनका ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल काफी घट गया था,

साथ ही वे गंभीर डिहाइड्रेशन और थकान से जूझ रहे थे। ज्ञात हो कि झारखंड के छात्र आंदोलनों का एक प्रमुख चेहरा बन चुके देवेंद्र नाथ महतो का जीवन संघर्षों और सार्वजनिक मुद्दों से भरा रहा है। देवेंद्र रांची जिले के राहे प्रखंड स्थित कापीडीह गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता विशंभर महतो एक सेवानिवृत्त सरकारी शिक्षक हैं। देवेंद्र ने साल 2006 में मैट्रिक, 2008 में साइंस से इंटरमीडिएट, 2017 में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातक और बाद में कुरमाली भाषा में स्नातकोत्तर (PG) व B.Ed की डिग्री हासिल की। कॉलेज के दिनों से ही छात्र हित के मुद्दों पर मुखर रहे महतो ने 2015 में तत्कालीन रघुवर दास सरकार की नियोजन नीति का विरोध किया। 2016 में छात्रवृत्ति में कटौती के खिलाफ सड़क पर उतरे। छात्र आंदोलनों के कारण जेल में रहने के बावजूद उन्होंने रांची सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ा और 1.48 लाख वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे। सिल्ली विधानसभा सीट से JLKM प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़कर 44 हजार वोट प्राप्त किए और पुनः तीसरे स्थान पर रहे। छात्रों की मांगों को लेकर लगातार आंदोलनरत रहने के कारण देवेंद्र महतो पर वर्तमान में 30 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं।

गौरतलब है कि इस पूरे आंदोलन की शुरुआत बीते 2 जुलाई को जेपीएससी 14वीं की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आने के बाद

हुआ। मुख्य परीक्षा के लिए कुल 2204 अभ्यर्थियों को योग्य घोषित किया गया था और परीक्षा की तिथि 18 से 20 जुलाई तय की गई थी। लेकिन परिणाम जारी होते ही धांधली के आरोप लगने शुरू हो गए। रिजल्ट में कैटेगरी-वाइज कट-ऑफ जारी नहीं किया गया। इसके अलावा जारी परिणाम पत्र पर जेपीएससी अध्यक्ष, सचिव या किसी सदस्य के हस्ताक्षर नहीं थे। सोशल मीडिया पर एक अभ्यर्थी की OMR शीट वायरल हुई, जिसमें केवल 48 प्रश्न हल करने के बावजूद उसे मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था। व्यापक विरोध के बाद मुख्य परीक्षा को तो रद्द कर दिया गया, लेकिन छात्र इस निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं। अभ्यर्थियों का सीधा आरोप है कि पेपर लीक किए गए और सीटें बेची गईं। छात्रों ने सीआईडी जांच को नकारते हुए पूरे मामले की जांच ईडी या सीबीआई से कराने की मांग की है। वही बता दें कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) से जुड़े देवेंद्र महतो ने 25 जुलाई को मोराबादी मैदान में गांधी प्रतिमा के समक्ष धरना शुरू किया था। शुरुआती दिनों में कम संख्या के बावजूद सोशल मीडिया के जरिए छात्रों का भारी समर्थन मिला। ऐसी खबर रही कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने वाले कॉकरोच

जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके भी आंदोलनकारियों को समर्थन देने के लिए रांची जाएंगे।

बहरहाल, झारखंड के रांची में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और अनियमितताओं के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) के 3 सदस्यों-अजीता भट्टाचार्य, अनिमा हांसदा और जमाल अहमद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य सरकार की सिफारिश पर इन तीनों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर सीआईडी के समन और छात्रों के भारी विरोध-प्रदर्शन के बाद यह कदम उठाया गया है। बता दें कि सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन मुख्य मांगों पर ठोस सहमति न बनने के कारण छात्र संगठनों ने 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। रांची में छात्रों और सरकार के बीच आज भी बैठक हुई। बैठक में कई अहम मुद्दों पर सहमति बनने की बात सामने आ रही है। हालांकि बैठक में वास्तव में क्या फैसला हुआ, इसको लेकर सरकार या छात्र पक्ष की ओर से अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। बैठक में 14वीं JPSC परीक्षा को रद्द करने पर सरकार के तैयार होने की बात सामने आई है। बैठक में सीआईडी की जांच रिपोर्ट 90 दिनों के भीतर देने की बात कही गई है। सरकार ने छात्रों को बैठक में सामने आए प्रस्तावों पर विचार करने के लिए समय दिया है। इससे पहले सरकार और छात्र संगठनों के बीच दिनभर बैठकों का दौर चला। आंदोलनकारियों ने साफ किया कि उनकी सभी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन के 16वें दिन बीतने के बाद झारखंड सरकार की 4 सदस्यीय मंत्रियों की टीम विभिन्न छात्र संगठनों और समूहों के साथ अलग-अलग दौर की वार्ता कर रही है। वही छात्रों के आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि, युवा अपने अधिकारों के लिए विरोध और आंदोलन कर रहे हैं। हमारी सरकार की कार्रवाई की वजह से ही उनमें आगे आने, विरोध करने और अपना हक मांगने की हिम्मत आई है, क्योंकि हमने गड़बड़ियों को उजागर किया है। युवाओं को न्याय मिलेगा और अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी।

संसद परिसर में किया गया एक 'प्रतीकात्मक ड्रामा' अब सियासी और कानूनी गले की फांस बनता नजर आ रहा है। अयोध्या राम मंदिर के 'चढ़ावा चोरी' के विरोध में भगवा वस्त्र पहनकर दानपात्र के साथ प्रदर्शन करना निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा सांसद अवधेश प्रसाद को भारी पड़ गया है। धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में धर्मनगरी वाराणसी के कोतवाली थाने में संतों की शिकायत पर इन तीनों दिग्गज नेताओं के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल, पूरा विवाद संसद भवन परिसर में हुए एक अनोखे विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है। आरोप है कि सांसद पप्पू यादव भगवा वेश धारण कर हाथ में एक सांकेतिक 'दानपात्र' लेकर बैठे थे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उस दानपात्र में कुछ पैसे डाले, जिसके तुरंत बाद पप्पू यादव दानपात्र लेकर भागते हुए दिखाई दिए। इस पूरे ड्रामे के जरिए विपक्षी नेताओं का मकसद अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे को उठाना था, लेकिन विरोध जताने का यह अंदाज अब एक नए विवाद की वजह बन गया है। भगवा कपड़ों में 'चोरी' का सीन फिल्माने पर हिंदू संगठनों और साधु-संतों का गुस्सा भड़क उठा है। बनारस के संतों का कहना है कि पवित्र भगवा वस्त्रों को चोरी जैसे कृत्य से जोड़कर पूरे हिंदू समाज और सनातन धर्म का अपमान किया गया है। संतों की इसी नाराजगी के बाद वाराणसी के कोतवाली पुलिस स्टेशन में राहुल गांधी, पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इस घटना के बाद से भाजपा और विश्व हिंदू परिषद ने मोर्चा खोल दिया है। भाजपा के पूर्व प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने हमला बोलते हुए पूछा कि क्या विपक्षी नेता किसी अन्य धर्म के प्रतीकात्मक कपड़ों में चोरी का ऐसा कोई नाटक करने की हिम्मत कर सकते थे? वीएचपी नेता आलोक कुमार ने भी इस पर कड़ा एतराज जताया है। दूसरी ओर, लखनऊ में विभिन्न संगठनों ने सड़कों पर उतरकर अखिलेश यादव और पप्पू यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनके पुतले भी फूंके। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संसद परिसर में किया गया यह विरोध प्रदर्शन 'इंडिया' गठबंधन पर ही भारी पड़ सकता है। इसे भाजपा और हिंदू संगठन 'हिंदुत्व और सनातन के अपमान' के तौर पर भुनाने में जुट गए हैं। ऐसे में रक्षात्मक मुद्रा में आई कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के लिए इस विवाद से पार पाना एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है।

बहरहाल, अयोध्या श्रीराम जन्मभूमि मंदिर हमेशा ही विश्व में सुर्खियों में रहा है-चाहे वह राम मंदिर आंदोलन हो, भव्य मंदिर का निर्माण हो या फिर सम्पूर्ण विश्व को साक्षी बनाने वाला राम लला का प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव। हाल ही में राम लला के चरणों में अर्पित चढ़ावे की चोरी की घटना के बाद, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था, चढ़ावा व गिनती की निगरानी, संपूर्ण सुरक्षा और VIP/VVIP दर्शन पास से जुड़े नियमों को पूरी तरह बदल दिया है और बेहद सख्त दिशानिर्देश लागू किए हैं। पारदर्शिता और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए चढ़ावे की पूरी प्रक्रिया को अब हाई-टेक निगरानी के दायरे में लाया गया है। दानपात्र खोलने से लेकर चढ़ावा गिनने तक की हर पल की रिकॉर्डिंग 360-डिग्री कैमरों और पेशेवर वीडियोग्राफरों (SLR और 360 डिग्री कैमरों से लैस) द्वारा की जाएगी। दानपात्र से जुड़ी पुरानी टीम को बदल दिया गया है।

निगरानी के लिए 8 सदस्यीय विशेष टीम बनाई गई है, जिसमें 2 बैंक कर्मी (भारतीय स्टेट बैंक), 2 ट्रस्ट प्रतिनिधि, 2 SIS सुरक्षा कर्मी, 2 पेशेवर वीडियोग्राफर शामिल हैं। परिसर में स्थित लगभग 40 दानपात्रों को अब एक साथ खाली करने के बजाय अलग-अलग दिनों में खाली किया जाएगा। सीलबंद बक्सों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों द्वारा विधिवत सील व हैंडल किया जाएगा। कोष प्रबंधन समिति के सदस्य जगदीश आफले ने स्पष्ट किया कि ट्रस्ट और भारतीय स्टेट बैंक के बीच किसी भी प्रकार का कोई गतिरोध नहीं है। पूर्व महासचिव चंपत राय, पूर्व ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्र एवं गोपाल राव की ID बंद होने के बाद श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ट्रस्ट ने अपने तीन चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) की ID को दर्शन पास जारी करने के लिए अधिकृत किया है। वर्तमान में अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन की देखरेख में श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन के प्रबंध किए जा रहे हैं। मंदिर के इतिहास में पहली बार सचिव पद पर जगदीश आफले को नियुक्त किया गया है, जिसकी आधिकारिक घोषणा 2 सितंबर को ट्रस्ट की बैठक में होगी। आफले को SBI में अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता भी बनाया गया है। दूसरी ओर मंदिर के आधिकारिक प्रवक्ता के लिए चयन प्रक्रिया अंतिम चरण में है। CEO पद के लिए 5200 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनकी स्क्रीनिंग और लिस्टिंग सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रमोद कोहली की अध्यक्षता वाली कमेटी कर रही है। वही श्रीराम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए त्रि-स्तरीय सुरक्षा प्रणाली लागू की गई है। CRPF (केंद्रीय सुरक्षा बल), PAC (प्रांतीय सशस्त्र बल) और SSF (विशेष सुरक्षा बल) के सैकड़ों जवानों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही AI-आधारित अत्याधुनिक CCTV कैमरे और स्मार्ट निगरानी प्रणाली लागू की गई है। परिसर की सुरक्षा के लिए 4 किलोमीटर लंबी परिधि दीवार और उच्च क्षमता वाले वॉच टावर स्थापित किए गए हैं।

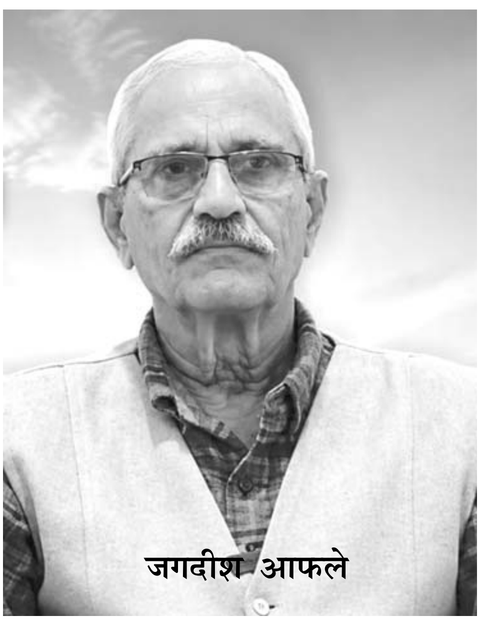

जगदीश आफले

सेवानिवृत्त न्यायाधीश
प्रमोद कोहली

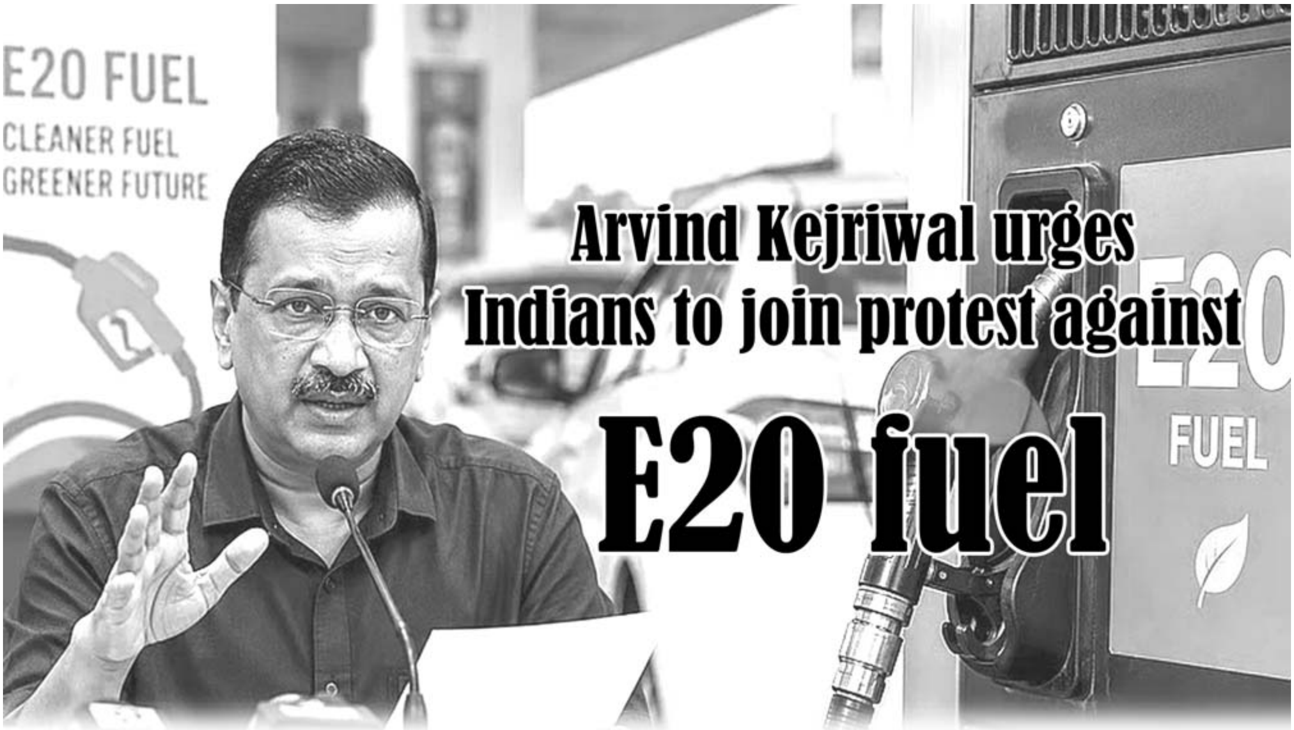

Arvind Kejriwal urges Indians to join protest against E20 fuel

Arvind Kejriwal, former Chief Minister of Delhi and a political rival of Prime Minister Modi, called on Indians to join his party's campaign against the Ethanol 20 fuel rollout. "If the public wants relief from E20, then they have to convene on the streets and on a very large scale," Kejriwal said in a press conference, after attempting to march on the Prime Minister's residence "with over 2,30,000 petitions against E20." Kejriwal accused Modi of buying large quantities of ethanol from the US "under pressure" from US president Donald Trump. "They are doing this in servitude to Trump, and the common man's vehicles are getting damaged as a result," he said in a post on X.

E20 petrol, a fuel containing 20% ethanol, has come under scrutiny after viral social media posts claimed it reduces mileage, harms engines and raises maintenance costs in vehicles designed for lower ethanol blends. The government has previously said it introduced E20 fuel only after rigorous testing. Despite protests from opposition leaders and public concerns, it is pushing ahead with its E20 biofuel strategy, aimed at reducing its dependence on imported oil and lowering emissions. On Monday, the government firmly ruled out any plans to rollback E20 fuel or move to the E10 fuel blend. India is not the first or the only country to be using ethanol in fuel. Countries including the US, Thailand, Brazil, Canada and France use various ethanol blends.

तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को
दुष्कर्म मामले में 10 साल की सजा

खोजी पत्रकारिता के लिए विख्यात मैगजीन 'तहलका' के संस्थापक और पूर्व एडिटर-इन-चीफ तरुण तेजपाल को बॉम्बे हाईकोर्ट ने वर्ष 2013 के चर्चित यौन उत्पीड़न मामले में दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने मई 2021 में निचली अदालत द्वारा तेजपाल को बरी किए जाने के फैसले को पूरी तरह रद्द कर दिया। कोर्ट ने उन्हें IPC की धारा 376 (2)(f) समेत अन्य गंभीर आपराधिक धाराओं के तहत दोषी ठहराया है। दरअसल यह पूरा मामला नवंबर 2013 का है, जब गोवा के एक 5-स्टार होटल में 'तहलका' मैगजीन द्वारा एक हाई-प्रोफाइल वार्षिक कार्यक्रम 'थिंक फेस्ट' आयोजित किया गया था। इस भव्य आयोजन में देश-विदेश की कई जानी-मानी हस्तियां शामिल हुई थीं। कार्यक्रम के दौरान (7 और 8 नवंबर 2013 की मध्यरात्रि) तरुण तेजपाल ने तहलका में ही कार्यरत अपनी एक जूनियर महिला पत्रकार (सहकर्मी) को लिफ्ट के अंदर रोककर उनके साथ दो बार जबरदस्ती की और यौन उत्पीड़न किया। घटना के कुछ दिनों बाद पीड़िता ने संस्थान की तत्कालीन मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी को ईमेल भेजकर अपनी आपबीती सुनाई। जब यह मामला सार्वजनिक हुआ, तो मीडिया और राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया। मामला बढ़ता देख तरुण तेजपाल ने पीड़िता को एक ईमेल भेजा, जिसमें उन्होंने अपने इस कृत्य को 'एक गलती' स्वीकारते हुए माफी मांगी। इसके साथ ही उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए 6 महीने के लिए 'तहलका' के एडिटर-इन-चीफ पद से हटने की घोषणा की। हालांकि, पीड़िता ने रुख साफ किया कि संस्था के प्रमुख द्वारा इसे महज एक व्यक्तिगत भूल बताकर मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है।

गौरतलब है कि 22 नवंबर 2013 को गोवा पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वत: संज्ञान लिया और तरुण तेजपाल के खिलाफ दुष्कर्म तथा गैर-जमानती धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की। 30 नवंबर 2013 को तेजपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। वह लगभग 8 महीने तक गोवा की जेल में बंद रहे, जिसके बाद जुलाई 2014 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल सकी। मई 2021 में गोवा की सत्र अदालत (सेशंस कोर्ट) ने इस मामले में तरुण तेजपाल को 'संदेह का लाभ' (Benefit of Doubt) देते हुए सभी आरोपों से बरी कर दिया था। सेशंस कोर्ट ने अपने फैसले में पीड़िता के घटना के बाद के आचरण पर सवाल खड़े किए थे, जिसकी देशभर के कानूनी विशेषज्ञों, महिला अधिकार कार्यकर्ताओं और आम जनता ने तीखी आलोचना की थी। निचली अदालत के इस विवादित फैसले के खिलाफ गोवा सरकार ने तुरंत बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ में अपील दाखिल की। बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस नीला गोखले और जस्टिस अमित जमसांडेकर की पीठ ने गोवा सरकार और अभियोजन पक्ष की दलीलों को स्वीकार करते हुए निचली अदालत के फैसले को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने पाया कि निचली अदालत का फैसला तथ्यों और कानून के सिद्धांतों के विपरीत था।

बहरहाल, हाईकोर्ट ने तरुण तेजपाल को निम्नलिखित धाराओं में दोषी पाया। धारा 376 (2)(f) (अधिकार या नियंत्रण की स्थिति में किसी महिला से दुष्कर्म करना), धारा 354(A) (यौन उत्पीड़न), धारा 354(B) (महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे

बता दें कि तेजपाल का जन्म 15 मार्च 1963 को पंजाब के जालंधर शहर में हुआ था। उनके पिता भारतीय सेना में थे, जिसके चलते उन्हें देश के अलग-अलग हिस्सों में रहने का मौका मिला। तेजपाल ने चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में स्नातक (ग्रेजुएट) की पढ़ाई की है। तेजपाल की शादी साल 1985 में हुई थी और उनकी पत्नी का नाम गीता बत्रा है। दोनों कॉलेज में साथ थे। उनकी दो बेटियां हैं, एक का नाम टिया और दूसरी का कारा है। 56 साल के तरुण तेजपाल भारत के प्रसिद्ध पत्रकार, लेखक और उपन्यासकार रहे हैं। उनके पास पत्रकारिता का 30 साल से ज्यादा का अनुभव है। साल 1980 में 'द इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप में नौकरी करते हुए उन्होंने अपने पत्रकारिता जीवन की शुरुआत की थी। इसके बाद 'इंडिया-2000' नाम की एक मैगजीन में नौकरी करने के लिए वे नई दिल्ली आ गए। 1984 में वे बतौर सीनियर सब-एडिटर 'इंडिया टुडे' मैगजीन के लिए काम करने लगे। 1994 में 'फाइनेंशियल एक्सप्रेस' को ज्वॉइन कर लिया। इसके बाद वे 'आउटलुक पत्रिका' के साथ जुड़े और अगले कई सालों तक वहीं काम करते रहे। इसी दौरान उन्होंने खुद की पब्लिशिंग कंपनी 'इंडिया इंक' शुरू की। ये वही कंपनी है, जिसने 1998 में अरुंधति रॉय का उपन्यास 'द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स' छापा था। जिसे बुकर प्राइज मिला था। 'आउटलुक' छोड़ने के बाद मार्च 2000 में उन्होंने एक अन्य पत्रकार अनिरुद्ध बहल के साथ मिलकर ऑनलाइन इंवेस्टिगेटिव वेबसाइट 'तहलका डॉट कॉम' शुरू की। साल 2004 में ये एक टैब्लॉइड न्यूजपेपर में तब्दील हो गई, वहीं 2007 में इसे मैगजीन का रूप दे दिया गया।

से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग)। फैसले के समय अदालत में मौजूद तरुण तेजपाल ने खुद को प्रताड़ना का शिकार बताया और अपनी उम्र तथा परिवार की स्थिति का हवाला देते हुए सजा में नरमी बरतने की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि वह दो बेटियों के पिता हैं। हालांकि, अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए उन्हें कम से कम 10 साल की सजा की श्रेणी में रखा है।

विडम्बना है कि तरुण तेजपाल एक भारतीय पत्रकार, प्रकाशक और उपन्यासकार हैं। वे चर्चित खोजी समाचार पत्रिका 'तहलका' के सह-संस्थापक और पूर्व प्रधान संपादक रह चुके हैं। उन्हें भारत में स्टिंग ऑपरेशन और खोजी पत्रकारिता के लिए एक समय जाना जाता था, लेकिन 2013 में एक महिला सहकर्मी द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद वे कानूनी विवादों में घिर गए।

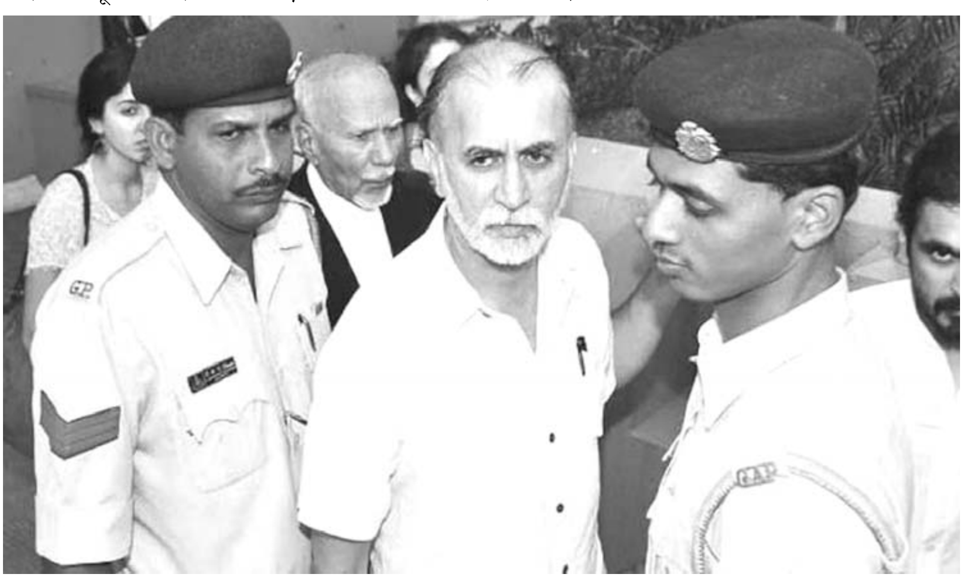

बहरहाल, एक महिला सहकर्मी द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद वे कानूनी विवादों में घिर गए। कोर्ट से दोषी ठहराये जाने के बाद तरूण तेजपाल ने कहा था, 'मैं 62 साल का हूं और मेरा मानना है कि मैं पीड़ित हूं। मेरी पत्नी है और इसके अलावा कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। मैं बस इतना कह सकता हूं कि हम अपील कर सकते हैं। कृपया मेरे साथ नरमी बरतें'।

गुजरात के मोरबी जिले के वीरपरडा गांव में एक 18 फीट गहरा कुआं इन दिनों लोगों की जिज्ञासा का केंद्र बना हुआ है। पिछले कई दिनों से इस कुएं का पानी बिना रुके समुद्र की लहरों की तरह ऊपर-नीचे हो रहा है। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल होने के बाद दूर-दूर से लोग इस अनोखे नजारे को देखने पहुंच रहे हैं। शुरुआत में लोगों ने इसे भूकंप, भूगर्भीय हलचल और यहां तक कि चमत्कार या अलौकिक घटना से जोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन अब भूवैज्ञानिकों ने इसकी अलग ही वजह बताई है।

☞ **समुद्र जैसी लहरें उठने से मचा कौतूहल, वायरल हुआ वीडियो :-** मोरबी तालुका के वीरपरडा गांव में किसान प्राणजीवनभाई सदारिया के खेत में बने इस कुएं का निर्माण करीब तीन महीने पहले ही हुआ था। करीब 30 फीट व्यास और 18 फीट गहरे इस कुएं में 2 अगस्त से लगातार पानी में तेज हलचल देखी जा रही है। कई बार पानी लहरों के साथ किनारों तक पहुंच जाता है और बाहर भी छलकने लगता है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आसपास के गांवों के लोग, राहगीर और पर्यटक बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचने लगे। हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर शांत खड़े कुएं में समुद्र जैसी लहरें कैसे उठ रही हैं।

☞ **लोग बोले- कहीं भूकंप का संकेत तो नहीं? :-** कुएं में लगातार उठती लहरों को देखकर लोगों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। कुछ लोगों ने इसे दैवीय चमत्कार बताया, जबकि कई लोगों को आशंका थी कि कहीं यह किसी भूकंप या भूगर्भीय हलचल का संकेत तो नहीं है। कुछ स्थानीय लोगों ने तो इसे अलौकिक घटना तक मान लिया। हालांकि जिला प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है और वैज्ञानिक कारणों का इंतजार करने को कहा है।

☞ **भूवैज्ञानिक ने बताया असली कारण :-** मोरबी के जिला भूवैज्ञानिक जगदीश वढेर के अनुसार, शुरुआती जांच में किसी भी तरह की भूकंपीय गतिविधि (Seismic Activity) के सबूत नहीं मिले हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण भूजल (Groundwater) का स्तर तेजी से बढ़ा है। इसके चलते जमीन के भीतर चट्टानों के सूक्ष्म छिद्रों (Pore Spaces) में फंसी हवा बाहर निकल रही है। यही हवा पानी की सतह पर दबाव बनाकर लहरें पैदा कर रही है। भूवैज्ञानिक ने यह भी बताया कि कुआं सड़क के किनारे स्थित है, जहां हवा का प्रवाह अधिक रहता है। इससे भी पानी की सतह पर हलचल बढ़ सकती है।

☞ **भूकंप से कोई संबंध नहीं, संस्थान ने भी दी पुष्टि :-** जगदीश वढेर ने बताया कि इस मामले में गांधीनगर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सीस्मोलॉजिकल रिसर्च (ISR) से भी संपर्क किया गया। संस्थान ने स्पष्ट किया है कि इलाके में कोई सक्रिय फॉल्ट लाइन (Active Fault Line) या भूकंपीय गतिविधि नहीं है। यानी इस घटना का भूकंप से कोई संबंध नहीं है।

☞ **अब गुजरात ग्राउंडवॉटर रिसर्च इंस्टीट्यूट करेगा विस्तृत जांच :-** मोरबी के जिला कलेक्टर स्वप्निल खरे ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद जिला भूवैज्ञानिकों ने मौके का निरीक्षण किया है। प्रारंभिक जांच में पानी की हलचल का कारण फंसी हुई हवा (Trapped Air) माना गया है। हालांकि अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए गुजरात ग्राउंडवॉटर रिसर्च इंस्टीट्यू की टीम को विस्तृत अध्ययन के निर्देश दिए गए हैं। टीम अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद इस अनोखी घटना की वैज्ञानिक पुष्टि हो सकेगी।

☞ **फिलहाल बना हुआ है आकर्षण का केंद्र :-** जब तक अंतिम रिपोर्ट नहीं आती, तब तक यह रहस्यमयी कुआं लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल इसे किसी चमत्कार, अलौकिक घटना या भूकंप से जोड़ने की बजाय वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। शुरुआती जांच साफ संकेत देती है कि यह प्राकृतिक भूजल पुनर्भरण (Groundwater Recharge) और जमीन के भीतर फंसी हवा के दबाव का परिणाम हो सकता है।

वैश्विक वित्तीय संस्था JP Morgan से जुड़ी एक चेतावनी के मुताबिक, वर्ष 2027 में दुनिया को बड़े खाद्य आपूर्ति संकट का सामना करना पड़ सकता है। भारत, ब्राजील और इंडोनेशिया उन देशों में शामिल हो सकते हैं, जहां इसका असर सबसे गंभीर रहने की आशंका है। इस संभावित संकट के पीछे भूराजनीतिक तनाव, उर्वरकों की कमी, कृषि लागत में बढ़ोतरी और अल नीनो से जुड़े बदलते मौसम के पैटर्न को प्रमुख कारण माना गया है।

☞ **2027 की पहली छमाही में महंगाई 5% तक पहुंचने का अनुमान :-** रिपोर्ट के अनुसार, 2027 के पहले छह महीनों में वैश्विक महंगाई करीब 5% तक पहुंच सकती है। इसकी तुलना में 2026 की इसी अवधि में यह करीब 2.8% रही थी। संभावित संकट केवल खाद्यान्न की कमी तक सीमित नहीं रहेगा। उत्पादन लागत बढ़ने और मौसम में अनिश्चितता के कारण किसानों के लिए फसल उत्पादन बनाए रखना भी मुश्किल हो सकता है। अगर खाद्य कीमतों में तेज वृद्धि होती है तो विकासशील देशों में परिवारों को अपनी आय का बड़ा हिस्सा जरूरी खाद्य वस्तुओं पर खर्च करना पड़ सकता है।

☞ **उर्वरक की कमी बढ़ा सकती है चिंता :-** संभावित खाद्य संकट में उर्वरक आपूर्ति एक महत्वपूर्ण कारक हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया के कुल यूरिया निर्यात में मध्य पूर्व की हिस्सेदारी करीब 42%, जबकि अमोनिया निर्यात में हिस्सेदारी करीब 27% है। हॉर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास तनाव और प्राकृतिक गैस की बढ़ती कीमतों से आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई है। रिपोर्ट में एक संभावित घटनाक्रम की ओर भी इशारा किया गया है। इसके अनुसार, संघर्ष से ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है, जिसके बाद उर्वरकों की कमी, कृषि लागत में बढ़ोतरी, उत्पादन में गिरावट और अंततः खाद्य कीमतों में वृद्धि हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, बाधित आपूर्ति व्यवस्था और उत्पादन को सामान्य स्तर पर लाने में एक से चार साल तक का समय लग सकता है।

☞ **अल नीनो से फसल उत्पादन पर बढ़ सकता है दबाव :-** अल नीनो से जुड़े मौसम में बदलाव वैश्विक कृषि पर दबाव और बढ़ा सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, अल नीनो के दौरान सूखा, बाढ़ और अन्य प्रतिकूल मौसम की घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। ऐतिहासिक आंकड़ों के अनुसार, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अल नीनो के कारण फसल उत्पादन में औसतन 3.5% की गिरावट देखी गई है। वहीं, एक शसुपर अल नीनोश वैश्विक खाद्य महंगाई को करीब 0.7% तक बढ़ा सकता है। यदि इसके साथ ऊर्जा की कीमतों में भी वृद्धि होती है तो इसका प्रभाव 1.3% से 1.5% तक पहुंच सकता है।

☞ **भारत पर भी पड़ सकता है सीधा असर :-** भारत में अगर मानसून कमजोर या अनियमित रहता है तो कृषि क्षेत्र पर सीधा असर पड़ सकता है। बारिश पर निर्भर धान, दाल, तिलहन, कपास और गन्ने जैसी फसलों पर बारिश के बदलते पैटर्न का प्रभाव पड़ने की आशंका है। भारत के सामने चुनौती केवल पर्याप्त अनाज उपलब्ध कराने की नहीं होगी, बल्कि उर्वरक और ऊर्जा बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच किसानों के लिए कृषि उत्पादन की लागत को वहनीय बनाए रखना भी होगी।

☞ **ब्राजील और इंडोनेशिया भी जोखिम वाले देशों में :-** रिपोर्ट में ब्राजील और इंडोनेशिया को भी संभावित खाद्य संकट से गंभीर रूप से प्रभावित होने वाले देशों में शामिल किया गया है। कृषि लागत में वृद्धि, फसल उत्पादन में कमी, उर्वरक की संभावित कमी और प्रतिकूल मौसम इन देशों में खाद्य आपूर्ति और कीमतों पर अतिरिक्त दबाव डाल सकते हैं। हालांकि, संभावित संकट का वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि आने वाले समय में भूराजनीतिक तनाव, उर्वरक की उपलब्धता, ऊर्जा कीमतों और मौसम की स्थिति किस तरह बदलती है।

☞ **अर्जुन पुरस्कार :-** तेजस्विन शंकर (एथलेटिक्स), प्रियंका गोस्वामी (एथलेटिक्स), नरेंद्र (मुक्केबाजी), विदित गुजराती (शतरंज), दिव्या देशमुख (शतरंज), धनुष श्रीकांत (बधिर शूटिंग), राजकुमार पाल (हॉकी), सुरजीत (कबड्डी), रुद्रांश खंडेलवाल (पैरा-शूटिंग), एकता भ्याण (पैरा-एथलेटिक्स), अरविंद सिंह (रोइंग), अखिल श्योराण (शूटिंग), त्रीसा जॉली (बैडमिंटन), गायत्री गोपीचंद (बैडमिंटन), लालरेम्सियामी (हॉकी), मुहम्मद अजमल (एथलेटिक्स), पूजा (कबड्डी)।

☞ **अर्जुन पुरस्कार (जीवनपर्यंत) :-** श्री आई अरुमैनायगम (फुटबॉल)

☞ **द्रोणाचार्य पुरस्कार :-** परवीर सिंह, छोटे लाल यादव, नेहा चव्हाण

☞ **द्रोणाचार्य पुरस्कार (जीवनपर्यंत) :-** धर्मेंद्र यादव, वीरेंद्र कुमार।

खेल मंत्रालय ने वर्ष 2025 के लिए किसी भी खिलाड़ी को प्रतिष्ठित ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं देने का फैसला किया जबकि 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना।इन पुरस्कारों के लिए छह महीने पहले सिफारिश की गई थी जिनका खेल मंत्रालय ने मूल्यांकन किया और किसी भी खिलाड़ी को खेल रत्न पुरस्कार नहीं देने का फैसला लिया। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अरुण कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने हॉकी स्टार हार्दिक सिंह को देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार के लिए नामित किया था लेकिन आखिर में वह दौड़ से बाहर हो गए। इससे पहले, 2014 में भी खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया था।विश्वकप विजेता शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख, डेकाथलॉन और ऊंची कूद के एथलीट तेजस्विन शंकर और बैडमिंटन खिलाड़ी गायत्री गोपीचंद उन 17 खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्हें मंगलवार को प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया।

अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित खिलाड़ियों में ग्रैंडमास्टर विदित गुजराती, गायत्री गोपीचंद की महिला युगल जोड़ीदार त्रीसा जॉली, ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों के रजत पदक विजेता मुक्केबाज नरेंद्र और युवा बधिर राइफल निशानेबाज धनुष श्रीकांत भी शामिल हैं।एशियाई खेल 1962 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे फुटबॉलर आई अरुमैनायगम को आजीवन उपलब्धि के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। इस वर्ष चयन समिति ने अर्जुन पुरस्कार के लिए 24 नामों की सिफारिश की थी, लेकिन मंत्रालय ने केवल 17 नामों को ही मंजूरी दी। पुरस्कारों की घोषणा करने में बहुत देरी हुई। खेल मंत्रालय ने योग के खिलाड़ियों को ही सम्मानित करने के उद्देश्य से पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया अपनाई। शतरंज खिलाड़ी 19 वर्षीय देशमुख विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। विदित गुजराती 2024 शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे।एशियाई खेल 2023 में डेकाथलॉन में ऐतिहासिक रजत पदक और पिछले साल एशियाई चौंपियनशिप में दूसरा स्थान हासिल करने वाले तेजस्विन शंकर ने घुटने की समस्या से जूझने के बावजूद राष्ट्रमंडल खेलों में एक कांस्य पदक जीता। वह उन खिलाड़ियों में शामिल थे जिन्होंने पुरस्कारों की घोषणा में देरी की आलोचना करते हुए इसे खिलाड़ियों के प्रति अनादरपूर्ण बताया।वर्ष 2024 में रिकॉर्ड 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिनमें से 17 पैरा-स्पोर्ट्स से थे। इस बार पैरा-स्पोर्ट्स से केवल दो नाम ही अंतिम सूची में शामिल हो पाए।

पैरा विश्व चौंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पैरा क्लब की थ्रोअर एकता भ्याण और पैरा विश्व कप 2024 के स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज रुद्रंश खंडेलवाल को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है। हालांकि, इस सूची में किसी भी क्रिकेटर का नाम नहीं है। मोहम्मद शमी को 2023 में अर्जुन पुरस्कार दिए जाने के बाद कोई भी क्रिकेटर इस पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया है। मंत्रालय ने तीन द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेताओं के नाम घोषित किए हैं।देश का सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न में एक पदक, प्रशस्ति पत्र और 25 लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाता है, जबकि अर्जुन पुरस्कार विजेता को 15 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। पिछले साल खेल रत्न पुरस्कार चार खिलाड़ियों को दिया गया था। इनमें विश्व चौंपियन शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश, पुरुष हॉकी कप्तान हरमनप्रीत सिंह, पैरा-एथलीट प्रवीण कुमार और निशानेबाज मनु भाकर शामिल थे।ये पुरस्कार परंपरागत रूप से हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में प्रदान किए जाते हैं, जो भारत के महानतम खिलाड़ियों में से एक हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती भी है। लेकिन अब इसकी कोई तिथि निश्चित नहीं है। इस वर्ष पुरस्कार चयनसमिति में भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के उपाध्यक्ष गगन नारंग, पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी अपर्णा पोपट और पूर्व हॉकी खिलाड़ी एम एम सोमैया भी शामिल थे।

कानूनी सलाह

शिवानंद गिरि
(अधिवक्ता)
Ph.- 9308454485
7004408851
E-mail :-
shivanandgiri5@gmail.com

✯ सामान्य आशा एवं सामान्य उद्देश्य किस प्रकार का अपराध है एवं दोनों में क्या प्रमुख अंतर होता है?

सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य भारतीय कानून (IPC/भारतीय न्याय संहिता) के दो बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जो किसी अपराध में एक से अधिक लोगों के शामिल होने पर लागू होते हैं। मुख्य अंतर यह है कि सामान्य आशय में अपराध करने से पहले दिमागों का मिलन (पूर्व-योजना) जरूरी है, जबकि सामान्य उद्देश्य के लिए केवल एक गैर-कानूनी मंडली का सदस्य होना ही काफी है।

इन दोनों के बीच के अंतर को आसानी से समझने के लिए नीचे दी गई तालिका (Table) को देखें :-

मुख्य अंतर तालिका :-

अंतर का आधार	सामान्य आशय	सामान्य उद्देश्य
कानूनी धारा	धारा 34 (IPC)/नई संहिता में संबंधित धारा	धारा 149 (IPC)/नई संहिता में संबंधित धारा
न्यूनतम सदस्य	कम से कम 2 लोग होने चाहिए।	कम से कम 5 लोग होने चाहिए।
पूर्व-योजना	इसमें दिमागों का मिलना और पहले से बनी योजना जरूरी है।	इसमें पहले से योजना बनाना जरूरी नहीं है।
सक्रिय भागीदारी	घटना के समय व्यक्ति की सक्रिय भूमिका होनी चाहिए।	केवल उस गैर-कानूनी समूह का सदस्य होना ही काफी है।
अपराध का	यह केवल एक नियम है, अपने आप में कोई अलग अपराध नहीं है।	यह अपने आप में एक विशिष्ट (अलग) अपराध बनाता है।

❖ **सामान्य आशय को विस्तार से समझें :-**

☞ **दिमागों का मिलन :-** इसका मतलब है कि अपराध करने वाले सभी लोगों को पता था कि क्या होने वाला है और वे सब इसके लिए सहमत थे।

☞ **पूर्व-निर्धारित योजना :-** घटना से पहले या घटना के वक्त ही अचानक सबके मन में एक जैसा प्लान बनता है।

☞ **उदाहरण :-** यदि 'A' और 'B' मिलकर 'C' को पीटने की योजना बनाते हैं। 'A' रास्ता रोकता है और 'B' डंडे से मारता है। यहाँ दोनों का आशय (Intention) एक था, इसलिए दोनों बराबर के दोषी होंगे।

❖ **सामान्य उद्देश्य को विस्तार से समझें :-**

☞ **गैर-कानूनी मंडली :-** इसके लिए 5 या उससे ज्यादा लोगों का समूह होना जरूरी है, जिसका मकसद कोई गैर-कानूनी काम करना हो।

☞ **सक्रिय होना जरूरी नहीं :-** अगर आप उस भीड़ का हिस्सा हैं और भीड़ में से कोई अपराध कर देता है, तो आप भी दोषी माने जाएंगे, भले ही आपने खुद हाथ न उठाया हो।

☞ **उदाहरण :-** 10 लोगों की भीड़ किसी दुकान को तोड़ने जाती है। उनमें से 2 लोग दुकान में आग लगा देते हैं। बाकी 8 लोगों को भले ही नहीं पता था कि आग लगाई जाएगी, लेकिन वे उस भीड़ का हिस्सा थे, इसलिए वे भी दोषी होंगे।

✯ रिट कितने प्रकार के होते हैं?

भारतीय संविधान के तहत मुख्य रूप से पाँच प्रकार की रिट (राइट्स) होती हैं, जो मौलिक अधिकारों की रक्षा करती हैं और अदालतों द्वारा जारी किए गए आदेश हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण (हबीज कॉरपस), परमादेश (मैंडेमस), प्रतिषेध (प्रोहिबिशन), उत्प्रेषण (सर्टियोरारी) और अधिकार पृच्छा (क्वो-वारंटो). ये रिट नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और सरकारी अधिकारियों को उनके कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य करती हैं.

पाँच मुख्य प्रकार की रिटें :-

☞ **बंदी प्रत्यक्षीकरण (हबीज कॉरपस):-** किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लेने से बचाने के लिए, यह आदेश देता है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को न्यायालय के सामने पेश किया जाए ताकि हिरासत की वैधता की जाँच हो सके.

☞ **परमादेश (मैंडेमस) :-** यह एक सार्वजनिक प्राधिकारी को उसके कानूनी कर्तव्य का पालन करने का निर्देश देता है, जब वह ऐसा करने में विफल रहता है.

☞ **प्रतिषेध (प्रोहिबिशन) :-** निचली अदालत या न्यायाधिकरण को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्रवाई करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है.

☞ **उत्प्रेषण (सर्टियोरारी) :-** निचली अदालत या ट्रिब्यूनल के अवैध या गलत आदेश को रद्द करने या मामले को अपने पास स्थानांतरित करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है।

☞ **अधिकार पृच्छा (क्वो-वारंटो) :-** किसी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से धारण किए गए सार्वजनिक पद को चुनौती देने के लिए जारी किया जाता है, यह पूछता है कि 'किस अधिकार से?'

❖ **अतिरिक्त जानकारी :-**

☞ **अनुच्छेद 32 (संविधान) :-** सुप्रीम कोर्ट को इन रिटों को जारी करने का अधिकार देता है, जो मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए है।

☞ **अनुच्छेद 226 (संविधान) :-** उच्च न्यायालयों को मौलिक और कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ये रिट जारी करने का अधिकार देता है।

आवश्यकता

अगर आप में है आत्मविश्वास और तीव्र इच्छा, तो मौका है इसे पूरा करने का....

बिहार की सबसे लोकप्रिय पत्रिका

केवल सच

और

केवल सच TIMES

को बिहार के हर जिले, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर संवाददाता, विज्ञापन प्रतिनिधि (डोर टू डोर मार्केटिंग) एवं प्रसार के कार्य के लिए परिश्रमी एवं जुझारू युवक/युवतियों की आवश्यकता है।

योग्यताः-

जिला ब्यूरो	प्रखंड संवाददाता	पंचायत संवाददाता	विज्ञापन प्रतिनिधी
स्नातक उतीर्ण	स्नातक/इंटर	स्नातक/इंटर/मैट्रिक	स्नातक/इंटर/मैट्रिक

संपर्क करे:-

पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, कंकड़बाग

पटना-20, मो.- 9431073769, 9955077308

WESTERLIN DRUGS PVT. LTD.

(Serving nation since 1990)

WESTOCITRON
WESTOCLAV
WESTOFERON
WESTOPLEX
QNEMIC

AOJ
AZIWEST
DAULER
MUCULENT
AOJ-D
BESTARYL-M
GAS-40
MUCULENT-D

SEVIPROT
WESTOMOL
WESTO ENZYME
ZEBRIL

WESTERLIN DRUGS PVT. LTD. · Dispersing Happiness

WESTERLIN DRUGS PVT. LTD.

Industrial area, Fatuha-803201

E-mail- westerlindrugsprivatelimited@gmail.com

Phone No.:0162-3500233/2950008